Title: Continued General discussion on the Budget (General) for 1998-99 and Demands for Excess Grants No.13,14,17,65 and 81 in respect of the Budget (General) for 1995-96. Shri Yashwant Sinha replied to the debate. Motion under Consideration - adopted

15.00 hrs.

ाडा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत वर्ष १९९८-९९ का अर्थ संकल्प एक साहसिक कदम है। प्राथमिकता तथा उद्देश्य दोनों दृष्टियों से यह स्वागत योग्य है। बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा एवं रोजगार पर जहां बल दिया गया है वहीं रक्षा बजट पर व्यय में वृद्धि की जाना ि वशेष महत्व रखता है। नाभिकीय कार्यक्रम व अणु विस्तार कार्यक्रम में भी उल्लेखनीय वृद्धि निश्चित ही भारत को एक विशेष स्थान पर लाकर खड़ा करने की महत्वाकांक्षा का संकेत है। भारत कृषि प्रधान देश है। अभी तक इस क्षेत्र की उपेक्षा होती रही है, किन्तु पहली बार ५० प्रतिशत से अधिक की आबंटन में वृद्धि ने किसानों में एक विश्वास पैदा किया है। देश की लगभग ७५ प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। सरकार द्वारा यूरिया की कीमतों में वृद्धि की गई थी, किंतु उसे काफी कम किया गया है और विश्वास है कि वह वृद्धि वापस हो जाएगी। यहां किसानों को दिए जाने वाले क्रेडिट कार्ड की योजना भी अपने में एक अच्छा कदम है। ग्रामीण विकास के लिए उठाए गए कदम भी सराहनीय हैं।

सभापति महोदय, कृषि के साथ शिक्षा पर की गई वृद्धि भी स्वागत योग्य है। देश में बढ़ती हुई आबादी और निरक्षरों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने तथा देश को साक्षर देश की श्रेणी में लाने का उत्तम प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था व समाधान की दृष्टि राष्ट्रीय एजेंडा के अनुरूप बजट में व्यवस्था करना अपने कथन को वास्तविकता में परिणत करने का उदाहरण है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा रक्षा पर आबंटन में वृद्धि कर देश को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है कि भारत सुरक्षित है। हमें पड़ोसियों की धमकियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है।

महोदया, कुछ अन्य बातें भी हैं जिनका भार आम आदमी या विशेष कर मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर पड़ सकता है वह है अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे या अन्य डाक दरें। मुझे विदित है कि इसमें कमी की जाकर जनाकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें राहत दी जाएगी। सेवाकर या टैंट हाउसों पर कर की वापसी भी आम आदमी को राहत देगी। आज हम आर्थिक दृष्टि से भूमंडलीकरण या ग्लोबलाईजेशन की चर्चा करते हैं। निश्चित ही बहुत से मामले ऐसे हैं जिन्हें अन्य देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापारिक संबंध की दृष्टि से देखा जाना जरूरी होता है और उसी दृष्टि से आयात-निर्यात के मामले में जैसे

---

* Speech was laid on the Table.

उत्पादकर, बिक्रीकर या आयात कर आदि को सुसंगत बनाने की पूरी चेष्टा की गई है। यही कारण हे कि उद्योग जगत ने इस बजट को संतुलित और व्यावहारिक बताया है। उपहार कर की समाप्ति भी एक उल्लेखनीय कदम है। बजट में कुछ नई प्राथमिकताएं की जा रही हैं। स्वदेशी को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी कुछ व्य वस्थाएं हैं। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में और विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। बिजली, परिवहन, दूरसंचार और बीमा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाएं और व्यवस्था भी एक परिवर्तन का संकेत देती हैं।

सभापति महोदया, कतिपय विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट को दिशाहीन और मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला कहा है, लेकिन यदि बजटीय प्रावधानों को गंभीरता से देखा जाए, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिलता है। दिशाएं क्या हैं यह तय है । ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र को समुन्नत करने, देश को रक्षा के मामले में सुसज्जित करने और युवकों में आत्मविश्वास जगाते हुए वेकारी और बेरोजगारी समाप्त करने के संकल्प के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा है शिक्षा की दृष्टि से उसमें किया गया आबंटन एक स्वागत योग्य कदम है। इस बजट से महंगाई बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है तथापि वैश्विक या भूमंडलीय अर्थ व्यवस्था के चलते कहीं कोई थोड़ा बहुत असर भले ही नजर आए, लेकिन वह हमारे प्रयासों के कारण नगण्य होगा। फिल्म उद्योग को दी गई सहायता से कई लोगों को शंका है, लेकिन उनकी आशंकाएं निर्मूल साबित होंगी क्योंकि आजकल जिस प्रकार से सिनेमा जगत और उससे जुड़े लोगों की जीविका पर एक प्रश्नचिहन लग गया है वह हटेगा और दूसरी ओर इसमें उगने वाले काले धन पर भी अंकुश लगेगा। बड़ी हद तक उसकी रोक होगी।

महोदया, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक का दबाव भी हम पर होगा, किन्तु जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान है, स्वदेशी है और हमारा संकल्प है देश को आगे ले जाने का, तो हम उस पर भी काबू पाएंगे। उनके दबाव में हमारी योजनाओं में कमी माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा देश की अर्षव्यवस्था में नई जान डालने का प्र ायास किया है। अनिवासी भारतियों को भी एक अवसर दिया है कि वे अपने देश को समुन्नत बनाने के लिए आगे आएं। औद्योगिक क्षेत्र में एक आत्म विश्वास जगाने तथा निरंतर घाटे में चल रहे उद्योगों के कारण बढ़ते हुए मजदूर असंतोष को दृष्टिगत रखते हुए बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं। कुछ विशेष व्यवस्था की है

देश को पेट्रोलियम या तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भी काफी कुछ कहा गया है। बजट का स्वागत व सराहना सभी ओर से हुई है। कुछ माननीय सदस्यों को यूरिया व पेट्रोल की कीमतों पर आपत्ति थी वह भी काफी हद तक दूर की गई है।

महोदया, अंत में पुनः वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों के व्यावहारिक सुझावों को देखें और तदनुरूप अपने उत्तर के समय उन पर आश्वस्त करें।

">

।श्री देवेन्द्र बहादुर राय (सुल्तानपुर): महोदय, आम बजट पर चर्चा में सहभागिता के लिए अवसर देने पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

भाजपा गठबन्धन के प्रधान मंत्री, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार का यह पहला बजट है। इस बजट को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय निवेशकों और उद्योगपतियों ने सराहा है। दुनिया के राजनैतिक एवं अर्थशास्त्रीगणों ने विभिन्न उन्नतशील देशों द्वारा प्रतिबन्धों को देखकर सुखद आश्यर्य व्यक्त किया है।

वर्तमान बजट पर चर्चा करने से पूर्व देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था पर विहंगम दृष्टि डालना उचित होगा। सन् १९९२-९३ से प्रारम्भ उदारीकरण के प्रथम चरण में उद्योग क्षेत्र में विकास तो हुआ, परन्तु कृषि क्षेत्र में केन्द्र सरकार एवं विदेशी निवेशकों ने पूंजी तो लगायी, परन्तु कृषि क्षेत्र में न तो सरकार ने और न ही विदेशी निवेशकों ने कोई पूंजी लगाई। स्पष्ट था कि कृषि क्षेत्र पिछड़ गया।

GDP

का ३० प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है। विगत दो वर्षों से उद्योग में भी विकात की गति रुक गई है और मन्दी का दौर चल रहा है। इन सभी चुनौतियों को इस बजट ने स्वीकार किया है।

प्रत्येक बजट में कुछ कमी रह जाती है, परन्तु बजट वही अच्छा है, जिसमें दिशा हो और अच्छाइयां अधिक हों. अच्छ बजट के रूप में कृषि, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रकचर और सोशियल सैक्टर अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र

GDP

का ३० प्रतिशत प्रदान करता है और उपभोक्ता वर्ग ७० प्रतिशत उपलब्ध करता है। इसी को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री जी ने विगत वर्ष की तुलना में सिंचाई पर ५१७ करोड़ रुपए के स्थान पर ६७७ करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को दिए हैं। इसी क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी दो हजार के मुकाबले तीस हजार करोड़ रुपए का प्रा वधान किया है। यह एक सराहनीय कदम है। किसानों को क्रैडिट कार्ड देना भी एक नया कदम है।

महदोय, विगत वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया और हमारी अर्थ व्यवस्था पिछड़ गई, परन्तु इस बजट में ४५२५२ के स्थान पर ६११४६ करोड़ रुपए (३५ प्रतिशत की बढ़ोतरी) उपलब्ध कराकर अर्थ व्यवस्था की गति देने के लिए जोरदार प्रयास किया गया है।

महोदय, आवास पर जो अधिक जोर दिया गया है,उसका फल इस देश की अर्थ व्यवस्था के लिए वरदान के रूप में मिलेगा। गरीबों को मकान, बेरोजगारों को रोजगार, सीमेंन्ट, लोहा आदि उद्योगों के उत्साह का बोध होगा। इसी प्रकार विगत वर्ष के ४७१६ के स्थान पर ७०४७ करोड़ रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान करके ि वत्त मंत्री जी

---

*Speech was laid on the Table.

ने वर्तमान एवं नई पीढ़ी के लिए शिक्षा, रोजगार एवं सांस्कृतिक विकास के समुचित अवसर प्रदान किए हैं। रक्षा बजट पर १४ प्रतिशत से ज्यादा धन देकर वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से देश की सुरक्षा पर ध्यान दिया है, वह वन्दनीय है। अबी कांग्रेस की सम्मानित महिला सदस्य ने कहा कि रक्षा पर ज्यादा धन देकरर भाजपा के गठबन्धन सरकारे ने चुद्ध को लिए अपने को तैयार कर रही है। मैं आपके माध्यम से ऐसे आलोचकों को सन् १९६२ के भारत-चीन युद्ध की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। महोदय, उस समय की सरकार टैंक के कारखाने में ट्रैक्टर बना रही थी। हिमालय की बर्फीली सीमाओं पर सैनिकों को साधारण जूता और वर्दी दी गई थी। नतीजा क्या हुआ? हमारे हजारों जवान मारे गए, लाखों वर्गमील जमीन चीन के कब्जे में चली गई। रक्षा मंत्री हटाए गए और श्री नेहरु का सम्मान गिरा। दीवाली पर करोड़ों देशवासियों की आंखों में पानी भर आया और लता जी ने रोमांचक और दुखदायी गीत के बोल गाए। वर्तमान बजट की आलोचना नहीं, प्रंशसा होनी चाहिए। अब न शहीदी गीत गाए जायेंगे और न किसी पर्व पर आंसु बहाए जायेंगे। गाना ही होगा, तो वीर गीत हम गायेंगे।

अंत में, महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। विगत वर्ष के बजट चर्चा पर भी मैंने यह बात कही थी। इस ओर कोई प्रगति न होने के कारण मैं पुनः इस बात को यहां पर उठा रहा हूं। महोदय, पैसा एकत्रित करके अरबों रुपयों का बजट बनाया जाता है और लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है और उधार भी लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नाम प्रकार के विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है नहीं।

महोदय, वर्ष के चार माहों में बजट बनता है और अगले सात माह १५ दिनों लगभग ३० प्रतिशत बजट खर्च होता है, जबकि २० मार्च से ३१ मार्च के बीज लगभग ६० प्रतिशत से ७० प्रतिशत बजट खर्च होता है। यह एक क्रिमिनल वेस्टेज है। ऐसे लोगों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करनी होगी। केवल दस दिनों में अरबों का खर्च, खर्च नहीं बल्कि हेराफेरी है। वास्तव में तीन-तीन माह पर चर्चा होनी चाहिए और देश के पैसे को लूट के लिए प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पर कोई ठोस कदम उठाना होगा। पीने के पानी के लिए भी तीन माह के अन्दर एक विस्तृत योजना बनायी जाए अन्यथा भविष्य में अशान्ति का मुख्य कारण पीने के पानी का अभाव होगा।

महोदय, वर्तमान बजट का मैं समर्थन करता हूं। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अवसर प्रदान करने पर आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं।

">

।श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम जनरल बजट पर बोलने के लिए सूची में था लेकिन समय के अभाव में वार्ता में भाग न ले सका। अतः मेरा भाषण एवं सुझाव को वाद-विवाद में सम्मिलित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संसद में जो क्रांतिकारी बजट पेश किया है, उसके समर्थन में मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट से देश की आम जनता को लाभ मिलेगा, जो पचास वर्षों तक नहीं मिल पाया। इस बजट में गरीबों को, हर व्यक्ति को पानी की सु वधा, सड़कों एवं पुलों का निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा में अधिक धन खर्च करना, इन्दिरा आवास की संख्या बढ़ाना, ग्रामीण रोजगार में अधिक धन देना, बंद पड़ी सिंचाई योजना को चालू करना, गांव में बिजली की व्यवस्था करना, बीमार पड़े उद्योग को ठीक करना तथा वनांचल राज्य को अलग करना, अधूरी पड़ी

परियोजनाओं को पूरा करना जैसे बहुद्देशीय स्वर्ण रेखा परियोजना चाण्डील पश्चिम सिंहभूम के अधूरे कार्य को पूरा करना। इस प्रकार वित्त मंत्री द्वारा लाया गया बजट गरीबों के हित में है और यह सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए देश हित में लाया गया है। यह अत्यंत ही सराहनीय है।

परन्तु साथ-साथ मैं केन्द्र सरकार को सुझाव भी देना चाहता हूं कि सरकार धन हर विभाग को देती रही है और उस धन का दुरुपयोग होता रहा है। गरीबों के नाम पर लूट मचती रही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि पैसा ईमानदारी से खर्च हो और योजनाएं समय पर पूरी हों। अन्यथा धन का दुरुपयोग होगा जैसा कि पहले होता रहा है। हर योजना को चाहे सुनिश्चित रोजगार योजना हो अथवा इन्दिरा आवास योजना हो, जो धन केन्द्र सरकार देती है उसमें सांसद की भागीदारी अवश्य हो। सांसद की सलाह एवं अनुशंसा पर योजना स्वीकृत की जाये एवं दूसरी समीक्षा तीन महीने में हो तो योजनायें समय पर बन सकती हैं। चापाकल सिर्फ विधायकों को दिया गया है, सांसद को कुछ नहीं है। अतः सांसद को भी चापाकल का कोटा दिया जाये।

केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि भ्रष्टाचार पर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी योजना या कोई भी काम पूरा नहीं हो पायेगा। इसके लिए सरकार को शक्ति से पेश आना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करता है चाहे वह सरकारी नौकर हो या जन प्रतिनिधि, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी तभी भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है। बिचौलिये, दलाल हर जगह व्याप्त हैं, इन सब पर कड़ी निगरानी रखनी होगा और कार्रवाई करनी होगी तभी ईमानदारी से काम हो पायेगा। इसके साथ-साथ मैं केन्द्र सरकार से

---

*Speech was laid on the Table

अपने क्षेत्र रांची की कुछ ज्वलन्त समस्याओं के समाधान करने के लिए अनुरोध करता हूं।

१. बहुद्देशीय परियोजना चाण्डील, प. सिंह भूम का अधूरा कार्य को शीघ्र पूरा त

१

कराया जाये।

१

२. एच.ई.सी. धूर्वा को अधिक कार्य निर्देश दिये जायें एवं वहां के वरीय त

१

पदाधिकारियों को शीघ्र हटाया जाये। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एवं निदेशक

१

द रिटायर व्यक्ति हैं। वहां विज्ञापन द्वारा योग्य पदाधिकरियों की त

१

नियुक्त की जाये।

१

३. गोला, चाण्डील, भाया सिली, बन्ता, बारेन्दा सड़क जो चालीस वर्षों से बन त

१

रहा है, अभी तक अधूरा है। केन्द्र सरकार उसे अपने हाथ में लेकर अधूरी सड़क एवं पुलिया का कार्य पूरा कराये।

१

इ ी तरह रांची शहर जिसकी आबादी दस लाख की है, बाईपास सड़क नहीं बनी है। त

१

वहां बाईपास सड़क बनाई जाये। वनांचल राज्य का बिल इसी सत्र में लाया जाये। यूरिया की बढ़ी हुई कीमत पूरी तरह समाप्त की जाये।

१

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

।डा. रामविलास वेदान्ती (प्रतापगढ़): अर्थशास्त्र का सिद्धांत मांग व आपूर्ति पर आधारित है। मांग व आपूर्ति ही भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाती है और इसका स्रोत है मन। इतिहास साक्षी है कि मन की निरंकुशता ही भौतिकता, स्वार्थ परायणता, विवेकहीनता, अनैतिकता, कटुता, सामाजिक वैमनस्यता आदि का कारण रही है। इसकी परिणति ही संस्कृति, सभ्यता व राष्ट्र के विनाश के रूप में परिलक्षित होती रही है।

१

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी

१

यूनान, मिस्त्रों, रूमा सब मिट गए जहां से

१

वह 'कुछ बात' भारतीय मनीषियों ने प्रारम्भ से अनुभव किया - मन पर अंकुश का। आवश्यकताओं को सीमा में बांधने का। अपरिग्रह के महत्व को समझाने में। इस मंथन से उदघोषित हुआ 'सादा जीवन उच्च विचार' का सूक्त। यह सभी प्रयास मानवता, सभ्यता, संस्कृति को भौतिकता तथा बाजार की उपभोक्तावादी दानवों के ग्रास से बचाने के लिए किया गया।

१

मांग व आपूर्ति एक सिद्धांत है, किन्तु अर्थतंत्र की सुदृढ़ता उपभोग से नहीं बल्कि आय में बढ़ोत्तरी द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है। यही कारण रहा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आय नहीं बल्कि उपभोग पर अंकुश रखने पर बल दिया। लूट प्रवृत्ति के पोषकों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र रास नहीं आ सकते। ि वकासशील व गरीब देशों में अपने उत्पाद की खपत कर आर्थिक आधिपत्य की लालसा उन्हें चार्वाग के ऋणं कृत्वा घृतं पिवेति के सिद्धां के अधिक निकट ले जाते हैं। स्मिथ, प्लूटो व अरस्तु का बाजारी गणित उन्हें अधिक व्यवहारिक लगते हैं। स्वातंयोत्तर भारत में विसकित वेस्ट मीनिस्टर व्यवस्था के कारण पश्चिम के उ पभोक्तावादी सोच को इस देश में अपनी जड़ों को फैलाने में सकारात्मक सहयोग मिला और सन १९९१ के राजकीय खाद ने तो दोहन की इस प्रक्रिया को फलने-फूलने में गुणात्मक संवर्धन किया।

">

माननीय श्री अटल जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा गठबंधन की सरकार के वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत पहला बजट उपभोग पर अंकुश लगाने के भारतीय मानसिकता की झांकी अवश्य प्रस्तुत करती है जब आयकर की परिधि में क्रैडिट कार्ड तथा महंगें क्लबों के सदस्यों को रखने का प्रावधान रका गया। ढुलाई/मजदूरी करने वालों के स्थान पर चार्टर्ड एकाउटेंट, मैनेजमेंट सलाहकार, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सचिव आदि जैसे महंगे पेशा से संबंधित लोगों को आयकर के दायरे में लाया जाना निश्चित ही स्वागत योग्य प्रयास है। मैं एक कदम आगे बढ़कर वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करना

*Speech was laid on the Table.

चाहूंगा कि आंतरिक अर्थतंत्र की सुदृढ़ता के लिए उनका मंत्रालय उन आयों पर जिनका निवेश नये संस्था को खोलने, अनुसंधान/टैक्नोलॉजी के विकास में, रोजगार उपलब्ध कराने में या राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोग हो सके, को आयकर परिधि से सर्वता मुक्त करने पर सार्थक विचार करें। निश्चित ही इसका दूरभागी प्रभाव आंतरिक अर्थतंत्र के सुदृढ़ता पर पड़ेगा।

वैश्वीकरण ने शोषण का मीठा जहर फैलाने के उद्देश्य से नया भ्रम फैलाया-भूमंडलीकरण का। जबकि सच्चाई यह है कि समाज व राष्ट्र के उत्भव के साथ ही अंतरदेशीय व्यापार व पर्यटन अपने अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों/धर्मग्रंथों में वर्णित प्रागेतिहासिक काल में देवताओं/देवदूतों/पैगम्बरों के भ्रमण से लेकर मार्कोपोलो, वास्को-डी-गामा, सिन्दबाद, फाहियान, मेगस्थनीज, हवेनसांग तथा व्यापारियों/राजनयिकों द्वारा की गई यात्राएं इस कड़ी के रूप में देखे जा सकते हैं। हां, संचार व यातायात की आज की उन्नत टैक्नोलॉजी ने समय की बचत के साथ भूमंलीकरण के दुष्कर अवसर सभी के लिए सुगमता से उपलब्ध करा दिये हैं।

वैश्वीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण के माध्यम से विदेशी टैक्नोलॉजी व विदेशी निवेश के प्रलोभन दिये गए। हमनें आंतरिक अर्थतंत्र/टैक्नोलॉजी अंवेषण को वरियता देने की अपेक्षा मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तर्ज पर अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए विदेशी आकाओं के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिये। दौ सौ वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिछाये गए परतंत्रता के जाल को भी हम अपनी सनक में भूल गए। कितनी टैक्नोलॉजी आ पायी है विदेशों से और जो आयी भी उसका भी स्वदेशीकरण नहीं कर पाए। ढांचागत क्षेत्रों को, सुगमता से उपलब्ध आयातित टैक्नोलॉजी के हवाले कर छद्म विकास का ढिंढोरा पीटते रहे। हम यह भूल गए कि आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है। टेलीफोन यंत्र तक में हम स्वदेशी टैक्नोलॉजी नहीं ल सके। माइक्रो-चिप्स व सैमी-कंडक्टर डि वाइसेस के लिए हमें विदेशियों पर आश्रित रहना पड़ता है। डनलप द्वारा टायर/टयूब टैक्नोलॉजी हस्तांतरण करने से इंकार करने के कारण ही सीएट इंडिया जैसी बड़ी कंपनी को बिकना पड़ा। यह तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। सच्चाई यह है कि हमारी निर्षक्रयता के कारण ही हमारे भौतिक विकास का रिमोट कमोवेश अब ि वदेशियों के हाथ में है। टैक्नोलॉजी आयी है अवश्य लेकिन आलू चिप्स में खाद्य प्रस्सरण में, सौन्दर्य प्रसाधनों में, फूहड़पन तथा अपसंस्कृति को फैलाने में। अनुसंधान, विज्ञान व टैक्नोलॉजी मदों में उचित आवंटन कर वित्त मंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करने का एक प्रयास इस बजट द्वारा किया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

निठ्ठलापन के आदी व्यवस्था ने बहुत आसानी से उदारीकरण की आड़ में उधारीकरण को ही बढ़ाया है। आज स्थिति यह है कि कर के रूप में जनता से वसूले गए प्रति रूपए से लगभग चालिस पैसा ब्याज की भरपाई में ही जा रहा है, मूल ऋण तो अलग से यथावत ही है। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष १९९७-९८ में सरकार की कुल ऋण देनदारियां ७३४,००० करोड़ थी जिसमें से विदेशी ऋण ५६,००० करोड़। इसका अनुपातिक उपयोग ढांचागत क्षेत्रों के बजाय रेवड़ियां बांटने या बीमार इकाइयों की देनदारियों या फिर सरकारी रिसाव में ही अधिकतर हुआ है। इन पर हमें प्रतिवर्ष ६८,००० करोड़ रुपये का ब्याज देना पड़ता है। मैं ि वत्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ब्याज के इस चक्रव्यूह से भारत की जनता को मुक्त करने के लिए एक मुस्त अदायगी का विकल्प अनुपयोगी सम्पत्ति के विक्रय या स्वैच्छिक कोष की स्थापना के माध्यम से ढूंढने का प्रयास अवश्य करें।

जहां तक विदेशी निवेश की बात है उसका एक उदाहरण ही यथेष्ट होगा। हम १५ अरब डालर का खर्च प्रतिवर्ष सोना आयात में करते हैं। यह तो केवल एक ही मद की बात है जबकि विदेशी निवेश मिलता है २ या ३ अरब डालर। मैं प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। दिल्ली में सबसे अधिक पान की दुकान चलाने वाले प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के चौरसिया लोग हैं। अमुमानतः उनकी मासिक आय यदि पांच हजार भी मान ली जाए तो बचत में से हजार को कम से कम वे अपने परिवार के जीवन यापन के लिए भेजते ही होंगे। दिल्ली में अर्जित आय का कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ भी जाता है, और यह स्वभाविक भी है। यही सिद्धांत नि वेश करने वालों पर लागू होता है। भयावहता तब और भी बढ़ जाती है जब लूट संस्कृति के कारण न्यूनतम मर्यादाओं की उपेक्षा करते हुए लाभ बटोरने की अमानवीय प्रवृत्ति हावी हो जाती है। विदेशी निवेशकों की मानसिकता में ऐसा कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। एशियन टाइगर्स कहलाकर गुब्बारे की भांति फूले रहे इंडोनेशिया, थाईलैंड व मलेशिया का विदेशी निवेश पर आधारित आर्थिक हश्र हमारे सामने है। लैटिन अमरीकी देशों की दुर्दशा बी किसी से छिपी नहीं है। ऐसी दशा में आसन्न संकट को देखते हुए आंतरिक अर्थ तंत्र को सशक्त करने पर अधिक बल दिया जाना ही समय की मांग है। भविष्यद्रष्टा श्री अटल जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए आंतरिक उदारीकरण की एक पहल की है। बीमा क्षेत्र को भारतीय निवेशकों के लिए खोलना उसी की एक कड़ी है। भारतीय मूल के अप्रवासी भारतीयों के लिए बजट में प्रदान की गई सुविधा, निश्चित तौर पर निवेश तथा मुक्त बाजार का भारतीय संस्करण ही है। इससे आर्थिक तथा सांस्कृतिक लाभ राष्ट्र को होगा। आठ फीसदी अनिवार्य आयात शुल्क मृतप्रायः देशी उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जबड़े से बाहर निकाल कर प्रतियोगिता की एक पृष्ठभूमि ही नहीं प्रदान करती अपितु नौकरशाही के जंजार से मुक्ति का संकल्प तता टैक्स में दी गई राहत लघु उद्योगों के विकास में रामबाण सिद्ध होगी।

माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल दिशा-निर्देश में भाजपा गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में यह घोषणा कि गांधी जी के निर्धनतम व निर्बलतम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए वित्ती प्रावधान अपने आप में एक सकारात्मक क्रांतिकारी प्रयास है। स्वाधीनता के साथ-साथ हमारे यहां विभाजन की दो घटनाएं एक साथ हुई।एक भौगोलिक तथा दूसरी मानसिक। एक प्रत्यक्ष तथा दूसरी अप्रत्यक्ष। भारत व इंडिया इसके दो स्वरूप हैं। भारत जहां गांवों में बसता है, ७५ करोड़ आबादी वाला वह क्षेत्र जहां गांधी जी का निर्धनतम व निर्बलतम व्यक्ति निवास करता है। इंडिया को सजाने व संवारने के लिए जिसका पल प्रतिपल शोषण होता है। साउथ व नार्थ ब्लॉक में बैठने वाले अब तक यह नहीं देख पाए कि ५ रुपये की रोजाना आय पर जीवन यापन करने वाली देश की आधी आबादी का बारह रुपये प्रति बोतल बिकने वाली बिसलरी वाटर, पेप्सी या कोला या फिर महंगें फास्ट फूड या इटालियन पीजा से कहीं कोई लेना-देना भी है या नहीं। हमने यह अनुभव किया। वित्त मंत्री जी ने बजट प्रावधानों को ग्रामों की ओर मोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। कृषि योजना व्यय पर पचास प्रतिशत की बढ़ोत्तरी व किसान कार्ड एक उदाहरण के रूप में आज हमारे सामने हैं। मूलभूत ढांचागत क्षेत्रों को सशक्ता करने के लिए ३५ प्रतिशत अधिक धन का बजट में आवंटन स्वावलम्बी भारत के निर्माण के प्रति हमारी वचनबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।

१९७४ के नाभकीय परीक्षण को रोकने के लिए विदेशी निवेश जैसा कोई हौवा तब हमारे सामने नहीं था। आज परिस्थिति बदली हुई है। उदारीकरण के मसीहाओं के कारण हमारे ऊपर अनावश्यक अंकुश लगाने का प्रयास चल रहा है। हमसे आशा की जा रही है कि हम सीमित दायरे में रहें, कमजोर बने रहें, आज्ञाकारी बने रहें। यह एक कुचक्र है। देश की अस्मिता की रक्षा के लिए माननीय अटल जी ने इन घुड़कियों से विचलित हुए बिना एक साहसिक निर्णय लिया। देश आज अपने को गौरान्वित महसूस कर रहा है। स्वावलम्बन की दिशा में भी लोग प्रयासरत हो रहे हैं। एक पहल वित्त मंत्री जी ने भी की है। विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करते हुए इस पर आर्थिक प्रतिबंधों की छाया भी नहीं पड़ने दी। कुछ लोग इससे बहुत हताश हैं। पहले उनका आकलन आर्थिक प्रतिबंधों के कारण कठोर बजट रूपी मशाले का था। उनकी शंकाएं निर्मूल हुई। वे अब बहुत परेशान हैं, फिर विरोध का सूत्र ढूंढ ही लिया। काफी मेहनती है।रोना रोया जाने लगा कि बजट में आर्थिक प्रतिबंधों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संकुचित राजनैतिक सीमाओं के पार ही राष्ट्र निर्माण सम्भव है। यदि इस प्रकार की कोई सम्भावनाएं वास्तव में हैं तो एक जुट होकर नई अर्थ संस्कृति के निर्माण में सभी को अपना योगदान करना चाहिए न कि विरोध के लिए तर्कहीन विरोध।

हमारी अर्थव्यवस्था उदारीकरण की संस्कृति के चलते पोर्ट फोलियों इन्वेस्टमेंट, डब्लू.टी.ओ. डाईरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मुद्रास्फीति जैसे गूढ़ शब्द जालों में फंस कर रह गई है। तर्क दिया जाता है कि आर्थिक प्रतिबंधों से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। महंगाई इससे बेकाबू हो जाएगी। एक उदाहरण देना चाहूंगा। १९९१-९२ में मुद्रास्फीति १६ प्रतिशत के आसपास थी और बाजार में आटा तीन रुपये दस पैसा, आलू दो रुपया, चावल परमल छः रुपये प्रति किलो तथा सरसों तेल २८ रुपये लीटर बिक रहा था। १९९७ में यही मुद्रास्फीति बीस वर्षों के रिकार्ड निम्नस्तर यानि २.९७ प्रतिशत पर रही। लेकिन महंगाई में गिरावट के बजाए आटा बिका दस रुपया, आलू दस रुपया, चावल परमल बिका दस से चौदर रुपया प्रति किलो तथा सरसों तेल ४२ से ४५ रुपये प्रति लीटर की दर से। कहां गया मुद्रास्फीति व महंगाई का अंतर संबंध का तर्क। आंकड़ों का खेल अब बंद होना चाहिए। सच्चाई को ईमानदारी से आत्मसात करने का प्रयास होना चाहिए। निर्धनतम व निर्बलतम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस सदन के सम्माननीय सदस्यों को अपनी राय रखनी चाहिए। बजट प्रावधानों के साथ वित्त मंत्री जी ने एक रूप रेखा प्रस्तुत कर दी है। अब इस पर ईमानदारी से, सहयोगके वातावरण को बनाते हुए अमल का सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। नुक्ताचीनी करने की अपेक्षा यह अधिक प्रासंगिक है कि प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए व्यवस्थागत दोषों से यह सदन कैसे निपटेगा। इस पर विचार होना चाहिए। देश में कार्य संस्कृति हम किस प्रकार से प्रभावी कर पाएंगे यह सोचनीय विषय है। मैं समझता हूं कि हर सरकार के समक्ष यह समस्या खड़ी होती रही है। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि राष्ट्र निर्माण में राजनैतिक सीमाओं को तोड़ते हुए एक नई संस्कृति हम विकसित करेंगे, सकारात्मक पहल करेंगे। राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि मानते हुए सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे।

इस देश में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हो, स्वदेशी भूमि पर स्वदेशी गोबर की खाद का उपयोग हो, यूरिया की खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। रसायनिक खाद के प्रयोग से भूमि उसर हो रही है। गोबर की खाद भूमि का आहार है। भूमि सूखी रहती है, गोबर की खाद की कमी है। आठ कि.ग्रा. गोबर से २ क्विंटल खाद बनती है। गोबर से तरल खाद बनाकर पौधों को अधिक फायदा होता है। नेशनल इंस्टीटयूट फार ट्रेनिंग इंडसट्रियल इंजीनियरिंग मुम्बई में होती है। उस उपकरण से ही बैल का होर्स-पावर ७८६ वाट बिजली लगातार पैदा करता है।

भारत के प्रधान मंत्री ने नैरोबी में १० अगस्त ९१ को हुए अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में स्वीकार किया था कि हमारे बिजली घरों जिनकी अधिकारिक क्षमता २२ हजार मैगावाट है से अधिक ऊर्जा हमारे बैल प्रदान करते हैं। यदि उनको हटा दिया जाए तो बिजली उत्पादन पर २,५४० अरब डालर का पूंजी निवेश करना पड़ेगा। इस पर भी कृषि अर्थ व्यवस्था को गोबर की खाद और कंडे के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले सस्ते ईंधन की हानि होगी।

अतः गोवंश की सुरक्षा कर देश की सम्पत्ति को बचाना चाहिए। इस देश में ८ करोड़ बैल कृषि कार्य में लगे हैं। किंतु अब कम हो गये हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में बैलों की और आवश्यकता है। पर्यावरण की दृष्टि से। यह बजट बहुत ही अच्छा है। पूर्व सरकारों ने जमकर ऋण लिए और देश को बर्बादी के पथ पर

खड़ा कर दिया। आज की परिस्थिति में टैक्स द्वारा वसूले गये रुपये में लगभग ४० पैसे इस ऋण पर ब्याज की अदायगी में ही लग जाता है। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार १९९७-९८

में सरकार का कुल ऋण ७३४.००० करोड़ था जिसमें ५६.००० करोड़ रुपये विदेशी ऋण था। यदि सरकार इस ऋण को अदा कर दे तो प्रति वर्ष ६८.०० करोड़ रुपये के ब्याज की बचत हो जाएगी। जिससे नहरें और सड़कें पर्याप्त बनाई जा सकती हैं। इस ऋण की अदायगी के लिए सरकार को देखना होगा। यह बजट देश की गरीबी को समाप्त कर देश में समृद्धि लाना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं।

स्वत्व ही व्यक्ति की मूल ऊर्जा होती है। जिस समाज के व्यक्तियों मे स्वत्व का जागरण हो जाता है वही राष्ट्र वैभव और गौरव को प्राप्त कर लेता है। स्वत्व के जागरण का मूल स्रोत है स्वदेशी चिंतन।

आज देश निःसंदेह आर्थिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ओर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा लिये गये विदेशी कर्ज का भारी बोझ तो दूसरी ओर नाभिकीय परीक्षण के कारण लगाए गये विभिन्न आर्थिक प्रतिबंध। लेकिन इस संक्रमण काल में भी केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री ने एक स्वदेशी सर्वहितकारी बजट देकर जहां देश में स्वत्व जागरण का एक अनुष्ठान किया है वहीं सरकार के साहस, संकल्प एवं दृढ़ इच्छा शक्ति को भी उजागर किया है। इसीलिए तो अगर उन कथित विपक्षी नेताओं को छोड़ दें, जोकि सरकार के किसी भी कदम की आलोचना करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार एवं कर्तव्य मानते हैं, तो पूरे देश के अधिकांश अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, सम्पादकों, आर्थिक चिंतकों से लेकर आम गरीब व्यक्ति तक ने बजट की मुक्त कंठ से सराहना ही की है।

शायद यह पहला मौका है जब जमीनी हकीकतों के मद्देनजर बजट तैयार किया गया। यही कारण है कि कृषि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कल्याण क्षेत्र के साथ ही स्वदेशी कुटीर घरेलू उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया है। कृषि बजट पर ५० प्रतिशत की वृद्धि कर सरकार ने साबित कर दिया कि उसे सर्वाधिक चिंता देश की बृहत्तर जनता के रूप में अन्नदाताओं की है। जो इस राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की छाया में सूख रहे घरेलू उद्योग में पुनः हरित क्रांति लाने का भी ठोस प्रयास है। जिसके कारण रोजगार के अवसर में भी भारी वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तुओं पर कर की वृद्धि भी न्यायपरक कदम ही है। स्वदेशी के हित में ८ फीसदी अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है।

">*SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL (ERANDOL) : Hon'ble Speaker, I beg to lay my speech on the General Budget for the year 1998-99 on the Table on the House.

At the outset I congratulate the Hon'ble Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee and Hon'ble Finanace Minister, Shri Yashwant Sinha for their bold action to represent the revolutionary Budget. Sir, this Budget is a unique one and is the only Budget to consider the real problems of all the Indians.

This budget is good for all the Indian inhabitants dwelling in cities & villages.

I welcome the solution to the problems of agriculturists & rural masses. The true India is in Villages and the Government has taken very essential and proper steps to uplift the villagefolks. It is heartening to note that the plan allocation to the Ministry of Agriculture is by 58%. It is also heartening to note that Rs. 1627 crore have been kept for Rural Water Supply to benefit one lakh inhabitation - irrigation and water development programmes are welcomed. Various Steps to boost the morale and credibility of the farmers is praiseworthy.

In the Industrial field more attention is given to sustain the financial and market constraints. I welcome the support of Central Government to the ruining state of small & big industries. The Finance Minister reflected his image in improving the conditions of common men for their needs of food, clothing and shelter.

In the sphere of shelter he has brought various schemes of housing.

No progress of India would be achieved if we do not pay attention to infrastructure and therefore the steps taken in the direction of development of infrastructure in the Budget are most creditable. Moreover the Budget

provision of increased outlay to the tune of 35% in Energy, transport and communication is a well-voiced decision.

I must congratulate the Finance Minister for his consideration and previsions of enough increased funds for education, youth development programmes, free education to girls and so on.

---

*Speech was laid on the Table.

The Finance Minister has also considered various encouraging schemes on Finance and Capital Markets, inflow of capital through NRIs, Disinvestment in PSUs, Direct & Indirect taxes.

I once again congratulate the Hon'ble Prime Minister, the Finance Minister and the Government for presenting such an excellent Budget for all Indians.

">

।श्री इन्द्रजीत मिश्र (खलीलाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में मंत्रालय संभाला, उसपर विचार करें तो पाएंगे कि देश का आर्थिक विकास मात्र ५ प्रतिशत रह गया है। कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। औद्योगिक उत्पादन घटकर ४.२ प्रतिशत रह गया है। राजकोषीय घाटा ६.१ प्रतिशत हो गया है। पूंजी बाजार की स्थिति निराशाजनक है। रुपये की कीमत लगातार घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में साहसपूर्ण कदम उठाकर सरकार की नीतियों को लागू करने का प्रयास किया गया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास के उत्पादन की ओर आपने ध्यान दिया है। देश की सिंचन क्षमता जो अब तक मात्र ३७ प्रतिशत है, उसमें पर्याप्त वृद्धि हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आबंटित धनराशि सकल बजट का ५८ प्रतिशत निर्धारित कर एक सामयिक कदम उठाया गया है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम पर ६७७ करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है जो १९९७-९८ के बजट से ३० प्रतिशत अधिक है। किसान ऋण के लिए दर-दर भटकता था, उसे खेती पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण बैंकों में भ्रष्टाचार के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। सरकार ने नाबार्ड की शेयर पूंजी में ५०० करोड़ की भारी वृद्धि की है जिससे कृषकों की ऋण सुविधा काफी बढ़ेगी। साथ ही सरकार ने क्रैडिट कार्ड जारी करने की योजना बनाकर किसानों को सम्मानित किया है। कृषि उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सरकार से आग्रह है कि ग्राणीण बैंकों के पुनर्गठन तथा ग्रामीण एवं शहरी सहकारी बैंकों को देहात में मजबूती प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाएं तथा सहकारी बैंकों के संविधान में संशोधन कर सहकारी बंधुओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराएं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि देश में रिजर्व बैंक के निर्देश के बावजूद आज भी तमाम फाईनैंस कम्पनियां बिना किसी गारंटी के चल रही हैं तथा आए दिन अपना कार्यालय समेटकर गरीबों की गाढ़ी कमाई हजम कर रही हैं। इनपर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों की पूंजी जमा योजना को और आकर्षक बनाने के लिए ब्याज दर में वृद्धि की जाए।

---

*Speech was laid on the Table.

मेरा सरकार से आग्रह है कि जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास, सुनिश्चित रोजगार योजना, बाल विकास परियोजनाओं आदि जो रोजगार एवं विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उनपर प्रभावी नियंत्रण किया जाए तथा उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शइता लाई जाए।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेष का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं जहां का नौजवान रोजगार की कमी के कारण देश के कोने-कोने में मजदूरी तथा नौकरी के लिए दर-दर भटकता है। रोजगार न मिलने के कारण वहां का नौजवान अपराध जगत की ओर प्रवृत हो रहा है, लूटपाट बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग के नाम पर एकमात्र खाद का कारखाना गोरखपुर में है। वह भी गत कई वर्षों से बंद पड़ा है, उसे अविलंब चालू कराया जाए। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रोजगार परक कारखाने लगवाने की व्यवस्था कराई जाए। इस क्षेत्र में बिजली का नितांत अभाव है। विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना केन्द्रीय स्तर पर कराई जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विकास पैकेज तैयार कराया जाए।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके विकास परक बजट के लिए पुनः बधाई देता हूं।

">

।श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। यह विदित ही है कि भाजपा सरकार ने १९ मार्च, १९८९ को पदभार ग्रहण किया था और उस समय जो आर्थिक स्थिति थी, वह इतनी निराशाजनक थी जिसका जिक्र इस सदन में इससे पूर्व कई माननीय सांसद कर चुके हैं। विगत ५० वर्षो के दौरान भारतवर्ष में अधिकांश कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और इक्काकांग्रेस पार्टी के अन्दर भी अगर मैं कहूं कि लगभग एक परिवार का ही राज रहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दौर में कृषि का नकारात्मक विकास हुआ और वर्ष १९९६-९७ में जो खाद्यान्न का उत्पादन १९९ मिलियन टन था, वह १९९७-९८ में घटकर १९४ मिलियन टन रह गया। यह उन व्यक्तियों की नीतियों का ही परिणाम है जो किसानों के विकास की बात करते थे।

औद्योगिक उत्पादन जो मंदी के कारण मात्र ४.२ प्रतिशत रह गया था और अधिक कमजोर होने लगा था। राजकोषीय घाटे की स्थिति निरन्तर बिगड़ती गई और यह सकल घरेलू उत्पादन का ७.१ प्रतिशत हो गया। उस समय आधारभूत बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें लगातार बढ़ रही थीं और देश की अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर हालत में थी। विगत ५० वर्षों की नीतियों के पश्चात यह हम बताना चाहते हैं कि स्वदेशी क्या है और विदेशी क्या है? पीने का पानी भी गांव के लोगों को यह सरकार दे नहीं पाई थी। एक नहीं, लाखों गांव देश में ऐसे हैं जहां लोग पांच-सात किलोमीटर दूर पीने का पानी लेने के लिए जाते हैं। विद्युत की स्थिति भी बहुत खराब है। आज भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे गांव मिलेंगे जहां लोगों को विद्युत नहीं मिल पाई है। हमें ऐसी आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है।

हमने जो पोखरन परीक्षण किया, उसकी वजह से विदेशी खतरे भी बढ़े हैं। देशवासियों को आशंका थी कि इस बार बहुत सख्त बजट आएगा। देशवासियों को लग रहा था कि पता नहीं कितने टैक्स लगेंगे। पोखरन की वजह से देश की जनता मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि इस बजट में भारी कर लगेंगे लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहती हूं कि वे इन सारी परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए और उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसके कारण जो लोग ऐसा कह रहे थे कि बहुत टैक्स लगेंगे, उन्हें निराशा हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने उनकी आशंकाएं दूर कीं और वास्तव में एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसका

---

*Speech was laid on the Table.

देश के आम आदमी ने स्वागत किया है। इसका मजदूरों, किसानों, महिलाओं और आम कर्मचारियों ने स्वागत किया है। इसका समाज के लगभग सभी वर्गों ने स्वागत किया है।

पोखरन परीक्षण के बाद, बहुत से खतरे हमारे सामने आए थे लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे लगता है कि उन्होंने बहुत ही गम्भीरता से बजट प्रस्तुत किया है। यह कोई हल्के-फुल्के ढंग से लाया गया बजट नहीं है और न ही यह किसी घबराहट में लाया गया बजट है। वास्तव में, यह बजट सारी स्थितियों का आंकलन करके और आने वाले खतरे का भरपूर अहसास करने के बाद लाया गया बजट है।

आज आवास की समस्या सारे देश की प्रमुख समस्या बनकर रह गई है। किसी भी बड़े शहर या कस्बे में जाइए तो मकान को समस्या सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने मिलेगी।

आज देश में लाखों लोग ऐसे हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आई हूं। वहां बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है और वहां पर विद्युत और पानी की बड़ी गम्भीर समस्या है तथा सड़कें भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वह कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र घाटमपुर में उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु उपचारात्मक कदम उठाने की व्यवस्था करें। धन्य वाद।

।श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में जहां संसद में भी चर्चा हो रही है, वहीं बाहर सारे देश में भी इस पर चर्चा है। पहली बार आजादी के ५० साल बाद भारत के अंतिम आदमी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी समस्याओं को तथा कुछ तथाकथित ि वकसित देशों की अर्थ-व्यवस्था के हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ते हुए कुप्रभाव को आंकते हुए, वर्ष १९९८-९९ का बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने, अटल जी की प्रेरणा से, इस सदन में पेश किया है जिसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे कुछ मित्रों ने इस बजट को स्वदेशी छायाग्रस्त बजट कहा है। निस्संदेह उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि यह बजट स्वदेशी का पोषक है किन्तु मेरी दृष्टि में यह एक साहसिक बजट है। यह बजट पूर्व सरकारों के बजट की तुलना में उद्देश्य और प्राथमिकताओं की दृष्टि से अभूतपूर्व है। यह गरीबोन्मुख तथा विकासोन्मुख बजट है। इस बजट में कृषि के लिए ५८ प्रतिशत की वृद्धि दी गई है क्योंकि हिन्दुस्तान में ६ लाख ७० हजार गांव हैं तथा भारत की आबादी का ७० प्रतिशत हिस्सा गांवों में बसता है। यह ५८ प्रतिशत की वृद्धि गांवों में दी गई है जो राष्ट्र को एक नई दिशा देगी।

यह पहला मौका है जबकि कृषि व शिक्षा के लिए बजट आवंटन में ५० प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस सरकार के उद्देश्य और प्राथमिकताओं का यह स्पष्ट संकेत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की ग्रामीण जनता जल, जमीन और जंगल से जुड़ी हुई है जिसका बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। भारत की ७० प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है जिनकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि है। बड़े दुख का विषय है कि आज आजादी के ५० साल बाद भी हमारे देश की नदियां का पानी व्यर्थ बह रही हैं और हम उस पानी को रोक नहीं पाए। आज तक जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, उनमें अभी तक २५६ सिंचाई योजनाएं बनीं, जिनमें से सिर्फ ८५ सिंचाई परियोजनाएं ही हम बना पाए तथा १७१ परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं। आज तक की सरकारों ने कभी भी इन परियोजनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण कृषकों की स्थिति इस देश में चिन्ताजनक है।

मुझे इस बात का हर्ष है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कृषि पर आवंटन ५८ प्रतिशत बढ़ाकर इस सफल रणनीति का उदघोष किया है। मुझे विश्वास है कि इस बजट का लाभ हमारे किसानों तक पहुंचेगा और यह नीति भारत के विकास में सहायक सिद्ध होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को उचित किस्म के उर्वरक उचित दाम पर मुहैया कराने होंगे एवं उर्वरकों का मूल्य काफी हद तक स्थिर रखना होगा। अभी जो यूरिया की कीमतें कुछ बढ़ी हैं, उसे कम

---

*Speech was laid on the Table.

करने का आग्रह हमने माननीय प्रधानमंत्री जी व वित्त मंत्री जी से किया था । उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास है कि यूरिया की कीमत इस बजट में कम कर दी जाएगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि सरकार ने ५८ प्रतिशत जो कृषि का बजट बढ़ाया है, वह बजट सही रूप से उसी जगह लगे जहां के लिए वह है। यह बजट बीच में लीक नहीं होना चाहिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम दिल्ली से एक रूपया भेजते हैं तो गांव में सिर्फ दस पैसे ही लगते हैं। मेरा आग्रह है कि दिल्ली से भेजा गया पैसा गांवों के विकास पर पूरा खर्च हो और बीच में उसकी कहीं लीकेज न होने पाए। मैं वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि किसानों के लिए नई तकनीक, उन्हें आधुनिक शिक्षा मिले, इस बात का हर संभव प्रयास होना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि कृषि हमारे विकास की पूंजी है और कृषि से ही हमारा विकास, संबल और स्थिर होगा।

सिंचाई और कृषि दोनो का चोली-दामन का संबंध है। हमारे देश में आज ५० साल बाद भी ३७ प्रतिशत कृषि योग्य जमीन की सिंचाई होती है और यही सिंचित जमीन है। मैंने अभी पहले बताया कि आज तक कुल २५६ परियोजनाएं बनीं जिनमें से सिर्फ ८५ परियोजनाएं ही पूरी कर पाए तथा १७१ परियोजनाएं अभी लम्बित पड़ी हुई हैं। आज हमारे देश में बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचता है तो कहीं देश में सूखाग्रस्त क्षेत्र भी हैं जबकि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में उत्तर से पूर्व की ओर ढलान है जिससे बरसात के दिनों में गिरने वाला पानी नदियों के माध्यम से बिखराव करके फसल, जमीन तथा जनमानस को हानि पहुंचाता है तथा ऊंचे क्षेत्र का पानी बरसात में निचले क्षेत्रों की ओर ही आता है। इस पानी को रोकने के लिए क्या हमारे पास शिक्षाविद विद्वान नहीं है। जब हमारे वैज्ञानिक देश में एटम बम बना सकते हैं तो वे इस पानी को भी रोक सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर ध्यान दे ताकि हमारी कृषियोग्य जमीन में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सके। यह किसानों के लिए नया कीर्तिमान होगा।

मैं मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जल से संबंधित कई विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त से झगड़ा होता है, पानी के लिए राज्यों में कलह पैदा हो रहे हैं - हमें इन विवादों का निदान करना होगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस दिशा में शीघ्र ही समुचित कदम उठाएगी ताकि पानी किसानों को मिले और हिन्दुस्तान की तरक्की हो। हिन्दुस्तान की तरक्की खेत-खलिहानों से होगी और खेत-खलिहान हरा तब होगा जब कृषि के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

मैं शिक्षा पर बजट में किए गए प्रावधानों के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा पर ५० प्रतिशत बजट बढ़ाया है। मेरा मानना है कि शिक्षा व रोजगार का सीधा संबंध होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो नई पीढ़ी को स्वावलम्बी बनाए, न कि बेरोजगारी को उन्मुख करे। हिन्दुस्तान में आजादी के ५० साल बाद भी लार्ड मैकाले की शिक्षा का प्रचलन है ।

इस शिक्षा से आज हमारी पुरानी संस्कृति का कोई सम्बन्ध नहीं है । आज का युवक इस पाश्चात्य शिक्षा को पाकर के अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और राष्ट्र प्रेम को भूल जाता है । वह भूल जाता है कि हमारे प्राचीन काल में जो वेदों के आधार पर शिक्षा थी वह हमारी संस्कृति पर आधारित थी । मैं शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमारी पुरानी शिक्षा पद्रति ही असली शिक्षा पद्रति है उसे रोजगारन्मुख होना चाहिए । आज हमारा बी.ए., एम.ए. पढ़ा नवयुवक नौकरी के लिए दौड़ता है । शिक्षा में ऐसा समायोजन हो जिससे शिक्षा बेरोजगारी को मिटा सके और माननीय वित्त मंत्री जी ने १०० करोड़ रूपये का लड़कियों की शिक्षा का प्रावधान करवाया है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ क्योंकि एक लड़की को पढ़ाने से दो परिवार शिक्षित हो जाते हैं । मैं हमारे शिक्षाविद मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस शिक्षा को रोजगारन्नमुख शिक्षा बनायेंगे ।

मान्यवर, मैं स्वास्थय के बारे में भी कहना चाहता हूँ । स्वास्थय सेवाों की बेहतरी के लिए वित्त मंत्री जी ने महत्वपूर्ण छूट दी है । मान्यवर विश्व स्वास्थय संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक २५० नागरिकों पर एक बिस्तर होना चाहिए । हमारे देश में आजादी के ५० साल बाद भी २९ लाख बिस्तरों की कमी है जबकि ७-८ लाख बिस्तरों की ही व्यवस्था हो पाई है और वो भी सिर्फ शहरों में जबकि हिन्दुस्तान की ७० प्रतिशत आबादी गांवो में रहती है । आज भी गांवो में हिन्दुस्तान के डाक्टर रहना पसन्द नहीं करते वह शहरों में रहना पसन्द करते हैं, उसका कारण यह है कि आज तक देश की आबादी के ५० साल बाद भी गांवो में रहने की कोई सुवुधा पिछली सरकारों ने नहीं दी । हमारे देश में डाक्टरों की कमी नहीं है । मैं माननीय स्वास्थय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गांवो में सुविधायें दें और गरीब आदमी तक हमारी स्वास्थय सेवायें पहुंच सकें । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्राथमिक स्वास्थय सेवायें विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए निःशुल्क व आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दी जायें । मैं सोचता हूँ कि पश्चमी देशों की नकल करके विज्ञापन पर अन्धाधुन्ध पैसा खर्च किया जा रहा है जबकि जरूरत है कुपोषम, कैंसर, टी.बी. जैसी

घातक बीमारियों को खत्म करने व उनके निदान करने की । साथ ही मैं यह चाहूंगा कि भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद) में भी रिसर्च हो, इस पदति को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि आज के एलोपैथी पद्रति जिसको हमारा गरीब व्यक्ति सहन नहीं कर सकता गर भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद) को लागू कर बढ़ावा दिया जाए तो हमारा हर नागरिक इस स्वास्थय चिकित्सा का लाभ हो सकेगा । मैं समझता हूँ कि यह चिकित्सा पद्रति सस्ती भी है और अच्छी भी है इसलिए इसका पूरे देश में ि वस्तार हो ।

मान्यवर, मैं इस विकासोन्मुख व गरीबोन्मुख बजट के लिए सरकार को विशेषकर वित्त मंत्री जी को साधुवाद देता हूँ । मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे द्रारा उठाए गये बिन्दुओं और सुझावों पर विचार करेगी तथा आशा करता हूँ कि नई सरकार और उसका बजट किसानों में आत्मविश्वास जगायेगा और उन्हें हर संभव सहायता देगा । मैं सरकार को पुनः बधाई देता हूँ कि तथाकथित विकसित देशों के आर्थिक प्रतिबन्धों के बावजूद भी दवाब मे न आकर देश को एक विकास पूर्ण एवं उद्देश्य पूर्ण बजट पेश किया है ।

">

।श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि मुझे बजट बहस पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। यह पहली बार हुआ है कि बजट ने कृषि और ग्रामीण विकास को एक विशिष्ट योग्यता प्रदान की है। यदि भारत को विश्व मंच पर अर्थ व्यवस्था का वैशिष्ट कायम करना है तो हमें अपने कृषि और ग्रामों को वरीयता प्रदान करनी होगी। मुंबई के सूचकांक से जो अर्थ व्यवस्था को नापते हैं, निश्चित ही वे इस बजट से निराश हुए होंगे। मैं चाहता हूं कि वे इससे नाराज न हों।

महोदय, इस बजट की आजकल विशेषतः अंग्रेजी अखबारों में बड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अंग्रेजी अखबारों की यह आलोचना ही इस बजट की सबसे बड़ी प्रशंसा है। जब शुरु में यह बजट आया था तो पता नहीं क्यों उन लोगों ने इस बजट की बड़ाई कर दी थी परंतु पढ़ने के बाद ज्यों-ज्यों उनको लगा कि गलती हो गई तो इस तरह का अखबारों में आने लगा, जो ठीक नहीं है।

महोदय, मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थ व्यवस्था आजादी के बाद पहले दिन से ही एक समस्या है और वह समस्या यह है कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था पर मनमाने साइनबोर्ड टांगते रहे हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारे मन में महात्मा गांधी के प्रति सम्मान था और हम गांधीवादी अर्थ व्यवस्था को साकार करने में लग गए थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ, अचानक यह अहसास हुआ कि नहीं, हमें गांधीवादी अर्थ व्यवस्था के बजाए समाजवादी अर्थ व्यवस्था लानी चाहिए। हमारी जो अर्थ व्यवस्था गांधीवादी थी, समाजवादी थी या उदारवादी थी, हमने अपनी अर्थ व्यवस्था के बारे में मौलिक चिंतन को सदा नकारा और उसी का परिणाम यह है कि हम विदेशी पैमानों से अपनी अर्थ व्यवस्था को नापते हैं, जिसकी वजह है कि अंग्रेजी अखबार एक ऐसे बजट की जो पिछले ५० वर्षों में एक अच्छा बजट आया है, उसकी आलोचना करने पर तुले हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब अगला बजट पेश करेंगे तो यह जो पूरा भारतवर्ष का धन है, संपदा है और जल है, जमीन है और जंगल है, जानवर हैं, उसके आधार पर अपनी अर्थ व्यवस्था को एक नया आयाम, एक नई दिशा वे जरूर देंगे।

हमारी अर्थ व्यवस्था में हमने अपने जो साइन बोर्ड बदले हैं, उसका बड़ा नुक्सान हुआ है। यह जो मंदी है, वह क्यों आई है। पिछले ५० सालों में समाजवाद के नाम पर हमारे देश की उद्यमशीलता को राहू सा लग गया है, क्योंकि केवल सरकारी उत्पाद ही नहीं, निजी उत्पादों में भी ९० प्रतिशत शेयर का खरीदार केवल सरकार रही है। अब यदि सरकार खरीदारी न करे तो भारत का उद्योग दौड़ायमान हो जाता है, डरने

---

*Speech was laid on the Table.

लगता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश की उद्यमशीलता का ाहवान करें।

महोदय, देश में जो बड़ी-बड़ी कंपनियां उत्पाद करती हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, तो ये उत्पादन शुल्क भी न दें तो यह कैसे हो सकता है कि इन सब पर उत्पादन शुल्क न लगे। इन पर उत्पादन शुल्क लगना ही चाहिए। माननीय वित्त मंत्री का यह निर्णय उचित है। इसमें एक बात जरूर विचारणीय है कि उत्पादन शुल्क के लिए ५० लाख टर्न ओवर की जो सीमा रखी है, जैसा महंगाई का जमाना है, उसमें वर्षभर में ५० लाख का टर्न ओवर हो गया है, महीने का ४ लाख टर्न ओवर हो गया है, जो एक छोटी दुकान का होता है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, आज सब लोग परेशान हैं। मैं उत्तर प्रदेश के खुर्जा संसदीय क्षेत्र से चुन कर आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में नोएडा जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, जहां पर बहुत से छोटे बड़े उद्योग-धंधे चल रहे हैं, वहां के लोग इस उत्पादन शुल्क से परेशान हैं। नोएडा में जहां टनों माल रोजाना बाहर जाता था, वहां के लोग चुप होकर बैठे हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हम वित्त मंत्री से निवेदन करके इस पर जरूर गौर करवाएंगे। खाद्य सामग्रियों को अपना नाम देकर तैयार किया और बेचा जाता है, इतने मात्र से वह ब्रांड हो जाता है और ५० लाख का टर्न ओवर बहुत कम होने से उसमें कवर हो जाता है। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि संभव हो तो इस टर्न ओवर को कम से कम २ करोड़ कर दीजिए। लघु उद्योगों की सीमा में उनको लाकर २ करोड़ टर्न ओवर तक उनको उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दीजिए, इससे ऊपर उत्पाद शुल्क लिया ही जाना चाहिए।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरी इन बातों पर जरूर गौर करेंगे और उपचारात्मक कदम उठाएंगे।

">*SHRI VINOD KHANNA (GURDASPUR): Sir, I would like to congratulate our Finance Minister, Shri Yashwant Sinha on presenting the Bharatiya Janata Party's maiden Union Budget. He had an unenviable task, having inherited a legacy of almost fifty years of inefficient handling of our economy.

As India enters the 21st century, there are many daunting challenges that face our great country. I believe that our Honourable Finance Minister has made a valiant effort to remedy the complex problems that face our nation. This Budget has provided a new thrust to our ailing economy by providing support in critical areas so as to catalyse growth, while displaying prudent fiscal management. Realizing that the economy had slowed down due to the absence of spending in the infrastructure sector and other core areas, the Finance Minister has sought to provide the needed impetus for the development of these crucial sectors.

Much has been said in support of the Budget, and I do not wish to repeat what has been stated. The essential areas addressed by the Budget are expansive, with the key features focusing on:

* Agriculture and Rural Development

* Small Scale Industry

* Private Investment in Industry

* Housing

* Infrastructure

* Education and the Youth

* Information Technology

* Finance and Capital Markets

* Non-resident Indians

* Public Sector Reform, and

* Direct and Indirect Taxes

---

*Speech was laid on the Table.

Sir, I hail from the film industry, and now represent Gurdaspur in Parliament, which is a largely rural constituency. On the face of it, there cannot be two more diverse worlds, one that appears to be ethereal, and one, which is rooted solidly in the earth. Yet it is the film world that has taught me a lot. one of my earliest lessons being "Mero Gaon Mera Desh". As the film profession took me often to the hinterland of India, I

realised that the essence and the future of India lie in its villages. So, I would like to concentrate on the provisions of the Budget dealing with agricultural and rural development, and the film industry.

Sir, I whole heartedly endorse the view that if there is one sector that has the potential to bring about a higher plane of economic growth and development in India, it is the agricultural sector. In fact, it is an area that demands the attention of the world.

The world over we see a shift from surplus to scarcity. By the year 2020, the population of the world is expected to go from 5.7 billion to 8 billion, and food output will have to increase from 1.8 billion tonnes to 3 billion tonnes just to keep up with the growth in population. With existing trends however, it is expected that declining grain outputs will lead to a grain shortage of 286 million tonnes by the year 2020. Agriculture will in the future be driven by the need to get more from the same resources. With the world fish catch stagnating at 115 million tonnes and milk output stagnating at 387 million tonnes, we will have to get more output from the land than from the sea. Even from the land, 80 per cent of growth will have to be through the intensification of outputs from existing lands, with an emphasis on multi-cropping, productivity, and a shift in focus to post-production operations.

India is the third largest agriculture produce in the world, being the largest producer of tea, sugar, fruits, vegetables and milk, and the second largest producer of rice. Yet, we have the largest wastage in the world. Thirty per cent of our fruits and vegetables and eight per cent of our cereals get wasted. Our food output is lagging behind our population growth, and to feed our increased population in the year 2020, we will have to increase our food output by 66 per cent over our current output.

In this scenario, I applaud Shri Sinha for giving due importance to the agricultural sector in his Budget, which is in line with our National Agenda of doubling food grain production, as stated by our Honourable Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajapaye.

Plan allocation to the Ministry of Agricultural has been increased by 58%, and that for the Watershed Development Programme has been increased 31%. the allocation for Accelerated Irrigation Benefit Programme has also been increased by 58%.

Sir, during my election campaign, an issue was made of a non-issue. It was falsely alleged that I did not even drink the water of Punjab. Sir, I relish the water of Punjab, and I believe that we are much more fortunate in Punjab that many of our brothers and sisters in the rest of our motherland, who are compelled to drink putrescent water. In the circumstances, I laud the allocation of Rs. 1627 crore for rural water supply which is to benefit one lakh habitations.

I fully endorse the marginal increase in the price of urea to protect the long-term health of our soil by restoring the balance on the use of nitrogenous, phosphatic and potassic fertilisers.

The Finance Minister may, however, consider exempting imported Naptha from the levy of 8% special, non-modvatable, additional duty of customs, as Naphtha is the basic raw material for the production of fertiliser industry. This eight per cent levy on Naphtha will lead to a cost push effect and effect domestic industry adversely, and in the long term will also impact the agricultural sector. I therefore urge the Finance Minister to kindly consider providing exemption to Naphtha from the levy of 8% special, non-modivatable ADC.

I commend the multi-pronged boost to rural credit in the Budget.

Sir, I believe that there is tremendous scope for improvement in our agricultural sector. Our potential is enormous. We can increase our output by 900 million tonnes per annum, which is worth US $ 78 billion, and is 150% of our current produce if we attain the same levels of productivity as our neighbours in China. We can generate 12 crores of additional employment from wasteland development alone. And we can increase our exports by Rs. 10,000 crores through the processing and export of the 30% wasted fruits and vegetables.

Sir, I have seen for myself that our farmers are as hard working as, if not more so, than those anywhere in the world. While they form the bedrock of our society and our economy, they have unfortunately not received the support they deserved from successive governments over the last fifty years or so. I, therefore, would once again like to congratulate our Finance Minister on giving due importance to agriculture sector.

Sir, while the film industry is extremely thankful to the Finance Minister for having considered some of its long overdue demands, on behalf of the film industry, I would like to bring to the attention of Shri Sinha a few anomalies. The film industry feels that additional customs duty of 8 per cent should not be levied on the import of positive and negative raw film as raw film is not manufactured in India at all, but is imported to the country. Similarly, the film industry urges that no additional customs duty of 8 per cent should be levied on the import of motion picture cameras, digital recording and mixing machines and laboratories' printing machinery as none of these items are manufactured in India.

Sir, whereas customs duty on Jumbo roles of colour positive and negative raw film has been reduced from 25 per cent to 10 per cent, we request you to instead apply this reduction in duty to finished roles of 1,000 ft. or 400 ft. each, as Jumbo roles are not imported into India.

Sir, the film industry is also hopeful that measures will be taken to rationalise the contradictory interpretations by the income tax authorities as regards Section 80 (II) (C) of the Income Tax Act. The film industry urges that income from the export of the Indian films be exempt from income tax, as is income from other exports.

Sir, with these words, I, once again, commend the Finance Minister on the Budget he has presented.

">15.01 hrs

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Mr. Speaker, Sir, I rise to reply to the discussion which has taken place in this House, spread over the last three days. But, before I proceed with the discussion on the Budget, I would like to respond to a very important issue which the hon. Member, Shri Natwar Singh has raised. Though it is not within the jurisdiction of the Ministry of Finance, still on behalf of the Government I would like to assure the hon. Member and the entire House that Kashmir is an inalienable part of India, will remain so and that there is no way in which anyone can coerce India into discussing Kashmir in any other forum except bilaterally with Pakistan. That is the policy of the Government and that will continue to be the position of the Government of India.

Mr. Speaker, Sir, we left this House this morning at 3.00 o' clock. The discussion on the Budget continued. Some really interested, faithful Members who wanted to express their points of view on the various aspects of the Budget stayed on, including some very senior leaders like Shri Motilal Vora.

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): When you said, `some faithful hon. Members', do you mean others are not faithful?

SHRI YASHWANT SINHA: No, I did not mean it.

SHRI MURLI DEORA (MUMBAI SOUTH): The others are more faithful as they were watching it on television.

SHRI YASHWANT SINHA: We carried on a long discussion. About 56 hon. Members of this House have taken part in the Budget discussion. I am grateful to each one of them for the interventions that they have made. I am particularly grateful to the Members of the Opposition for the positive aspects which they have identified and appreciated in the Budget. I am very grateful to the Members of the Treasury Benches that they have picked on the weeknesses of the Budget and pointed them out in this House. This has been the spirit in which this Budget has been discussed in this House, which is extremely encouraging for me.

Sir, we got off to a very impressive start by Shri Murli Deora opening on behalf of the Congress Party. I listended intently to what he had to say for almost an hour. I found that when he took off, he had on board our

friends from the Left who kept on appreciating, applauding and praising the remarks that he was making until he ditched them midway. And, when he started supporting some of the other aspects of the Budget, the Left kept quiet and they disassociated themselves from the approach which he was enunciating on behalf of the Congress Party.

SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): Then the Right took over!

SHRI YASHWANT SINHA: Yes.

We had a brilliant intervention from my immediate predecessor, Shri Chidambaram who kept the House spell-bound for nearly 60 minutes. Everyone listened to him with rapt attention including myself and I have taken copious notes of the points which he has made. I have taken copious notes of the points which have been made by all the hon. Members, and as I proceed it will be my endeavour to cover as many of the points which have been made as possible within the time at my disposal. While I say, Shri Chidambaram made an absolutely superb speech, the danger of the immediate predecessor speaking on the Budget of his immediate successor is always a little dicey. I recognised it and, therefore, when I was the Finance Minister for a brief period and Dr. Manmohan Singh succeeded me, I was the Member of the other House. I never intervened once in the Budget debate.

I go on to the philosophy and the other issue which Shri Chidambaram has raised, but I will refer to two issues right in the beginning because I found that he was trying to take some mileage out of these two issues which really when I enquired into the matter, I found that they were not perhaps the issues on which he should have tried to take that mileage.

He is not present in the House now. He had come to me after his intervention and he had told me that he had some urgent preoccupation in Chennai and he might leave. One of the issues on which there were cries of `shame, shame' from the Opposition benches was the issue of handlooms. Shri Chidambaram told the House that 84 lakh people were engaged in the handlooms sector; that that was one of the most important sectors and; that I had reduced the allocation in the Budget for the handlooms sector. I have checked it up in the expenditure statement of this year's Budget. I find that the only Head under which the handlooms budget has been reduced is the Head of Janata Cloth Scheme where the allocation has been reduced from Rs.30 crore in the RE of previous year to Rs.10 crore in the BE of this year. When I went into the detail I found that this reduction became possible because the Janata Cloth Scheme which was subsidised by the Government was closed down when Shri Chidambaram was the Finance Minister. I could not have made provision for a scheme which he had closed down. When I deduct that Rs.20 crore, I find that there is absolutely nothing in the Budget provision for the handlooms sector on which anyone could take any exception.

The other point which he raised -- on which my friend Shri Baalu immediately got up and demanded that the Finance Minister must immediately explain the position -- was the case of the Infrastructure Development Finance Corporation (IDFC), which Shri Chidambaram had set up when he was the Finance Minister. He said that though he located the headquarters of this institution in Chennai, the Board meetings were being held mostly in Mumbai. He was very angry. He asked as to why this was happening. He told me that I must do something immediately. I have checked up on the facts. The first meeting of the IDFC was held on the 5th of February, 1997. Until February, 1998, a period of 12 months, eight meetings of IDFC Board have been held, all this during the period when Shri Chidambaram was the Finance Minister. Except one meeting which was held in Chennai, all the other meetings have been held outside Chennai - six of them in Mumbai and one in Delhi. There is only one meeting which was held in May after I had taken over and that was held in Mumbai. I am told, without any intervention from my side, that the first Annual General Meeting of the IDFC is taking place on June 26, at Chennai. I have nothing to do with it. I do not claim any credit for it. They had already taken that decision. But the fact for which I will take credit before this House is that I have instructed the IDFC that they must, as far as possible, hold all their Board meetings in Chennai in future.

meetings at Chennai. The question was of having the headquarters located at Chennai. My point was whether you were going to have the headquarters of IDFC at Chennai or not.

SHRI YASHWANT SINHA: It is already located in Chennai.

As I said, the positive features of the Budget have been appreciated even by Members of the Opposition for which I am extremely grateful. But, some aspects have been strongly criticised. When my friend Shri Murli Deora was speaking on the Budget, he even read out from some media reports in the House on what somebody has said and some other commentator has said about this Budget. I have been left wondering, "After all, what is it that I have done in this Budget that I am being subjected to all this criticism?"

What is it? It has not taken me long to find the answer. The criticism is, Sir, it arises from the fact that I have tried to establish a balance in this Budget. Shri Chidambaram told me, "You should never talk of reforming the reform process." We have talked of reforming the reform process and we shall continue to talk of reforming the reform process until the reform process is reformed. And the criticism that I am facing as the Finance Minister of this country, of this Government arises out of the fact that we are trying to reform the reform process.

I have heard the debate which had taken place and which had again spread over three days on the problems faced by the farmers of this country, the suicides which they were committing. This House spent three precious days discussing that very very human and important issue. While delivering my Budget Speech, I said, it would be the endeavour of the Government to ensure that no farmer committed suicide, no farmer even went to jail for this.

Now, what is the commentary that I received. In one of the papers - I will draw the attention of Shri Maran, I will not name the paper, and I will not name the author - this is what the author has to say. I quote:

"If you sit back with your eyes closed during the early part of Mr. Sinha's speech, it could well have been Mrs. Gandhi holding fort."

It is very flattering for me to be compared to that great lady. When I am quoting, this Government is determined to create conditions so that no farmer goes to jail for a loan repayment default. Now, what is the further comment? Why a farmer on earth should be put above the law? I would like the House to take note of it. Never mind the survey across the length and breadth of the country would be hard put to come across many instances of anyone, least of all a farmer rotting in jail, because of non-payment of bank dues. They may be in jail for umpteen other reasons, but non-payment of bank dues is not one of them. This is the mindset. You talk about the farmers in this House, you will not be understood - I am not talking of this House, I am talking of outside, you will not be understood - it will not be appreciated, because I tried to establish a balance in this Budget. Balance of what? The balance was between agriculture, between rural development, between rural employment, between small scale industries, between housing, especially on the rural sector, between infrastructure, between something for the NRIs on the one hand and tax reforms, financial sector reforms, capital market, PSUs reforms, insurance, promotion of foreign direct investment on the other. This is the balance that I was trying to establish in this Budget and that is the reason why this Budget is being rubbished. I would like to say with all the emphasis at my command, Sir, that whatever be the criticism, as I said, in my Budget speech, if we have picked up the flag in our hand, nothing shall daunt us, we shall continue to march forward because that is the direction, that is the goal in which the Government would like to take the country.

There is no way in which we shall, as in the past, neglect the interests of rural community in order to please some other sections of society. It has been said, there is no focus. It is so because it is a balanced Budget. If it was imbalanced, then there would have been a focus. It has been said, it is a pedestrian Budget because I have talked of a common man in this Budget. Therefore, it is a pedestrian Budget. I accept the criticism. Shri Maran is not here. While quoting some newspapers he said that it lacks vision.

It is because other people have put on blinkers, that is why my Budget lacks vision.

Sir, there is a philosophy and this philosophy is not something which we crafted in the Budget. This is the philosophy on which all of us on this side of the House have been working for a long time. We have had our differences with the seven years of the reform process and I am making absolutely no secret of it.

When I was listening to Shri Bhajan Lal speaking from here on behalf of the Congress Party, with the best intention and best will in the world, I could not differ with him because he was talking of the Kisans of rural India, of rural development and saying all kinds of things which we have been saying when we were in the Opposition. Now, we always said and this is what we have reflected in our national agenda of governance that we shall proceed with reforms, we shall proceed with liberalisation. But the sequencing of the reform process is very very important and proper sequencing, as we understand it, enjoins upon us to first open up the internal economy. We must remove all those constraints in regard to the internal economy which still exists and thereafter we are saying, we must calibrate globalisation. Calibrate globalisation, this is what we are saying. We are against mindless globalisation and I would repeat it once again that that will continue to be our policy.

Shri Chidambaram also made the point that what is the philosophy of this Budget. You cannot spend your way to growth. You cannot achieve prosperity by spending. He said, `investments must be encouraged'. He was quoting his predecessor, Dr. Manmohan Singh in support of his thesis. I agree with him. I have no difference in approach. He tried expenditure, he tried to spend his way to growth but that is not the way I am planning expenditure in this Budget. It is not consumption expenditure which I am increasing like Shri Chidambaram did. It is investment expenditure in this Budget which I have enhanced significantly, considerably.

I have said, Sir, if I could quote from my Budget Speech briefly, that `as far as infrastructure is concerned, it is not merely the Government expenditure to provide a strong stimulus to infrastructure in larger public and private investment in these sectors' but also I recognise the role of investment. I recognise the role which investment must play in growth, both public as well as private, and that is the approach in this Paper. It is not consumption expenditure of which I am talking. When I have increased the plan to Rs.72,000 crore, which is an all time high, I am not talking of consumption expenditure when I have increased the expenditure over infrastructure, I am not talking of consumption expenditure. When I have increased expenditure over the rural infrastructure, I am not talking of consumption expenditure. Something like 10,000 to 15,000 crores of rupees worth of additional money is going to flow into the rural areas as a result of this Budget and that is going to generate demand.

What is the philosophy of this Budget? The philosophy of this Budget is that demand must be generated in order to give momentum to this economy and that demand will come from sectors where the largest number of our people live, from the rural areas. If the rural areas do not generate demand, there is no way in which only urban India, industrial India can go forward at the cost of rural India. Therefore, I have taken all those steps. It is not merely good social policy, it is good economics that demand must be generated. It is only when that kind of demand is generated that the investment demand will be generated. It is when that sector does well that we will be able to do well on the export front. That is the approach in this Budget.

Shri Murli Deora was very concerned and generally, I am also concerned at what was happening to the Bombay Stock Exchange.

No Finance Minister makes the Budget for the Stock Exchange, he makes the Budget for the people of the country. I am not disregarding the Stock Exchange. Mind you, I am not one of them. I do not believe in what one of my predecessors had said. ... (Interruptions)

SHRI MURLI DEORA: I had talked about the entire capital market of India and do not say, `Mumbai Stock Exchange'. The capital market is not confined to the Stock Exchange only. You know that. ... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: I will come to that.

Sir, I was looking at the figures. I am sure that my friend, Shri Murli Deora must be equally aware of them because he represents Mumbai. What has been the position in the last five years? After each Budget, there has been a steep decline in the Sensex. After each of the four Budget of Dr. Manmohan Singh and one of Shri P. Chidambaram, the Mumbai Sensex went down like anything. It was only once, in all these five, six years, only

once, after Shri Chidambaram's famous `dream Budget' of last year, the Sensex went up. Sir, I would prefer to be in the company of Dr. Manmohan Singh than in the company of Shri P. Chidambaram. I would like that the year should end as well as those years ended rather than the year of the famous `dream Budget' when the Sensex went up immediately after the Budget. I have great regard for Dr. Manmohan Singh. I had disagreed with Dr. Manmohan Singh then also when he said, `I do not lose my sleep over the stock market.' I worry about the stock market. I am concerned with the stock market also among other things. And, therefore, Sir, in the Budget, we had outlined a number of steps to improve the capital market. Did I not say that we would bring a law to bring trading in derivatives possible? I said it in my Budget speech. On that day, immediately after I read my Budget speech, I had also tried to find out what had depressed the market. That was because I did not say anything about buy back of shares. That is what it was. Now, my predecessor, Shri P. Chidambaram had made a mention of this. He said that the then Government was committed to buy back of shares. That Government went without implementing that. ... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आप यह भी बता दें कि चिदम्बरम साहब के समय लोन कितना बढ़ता था और आपके समय में कितना बढ़ा है।

श्री यशवन्त सिन्हा: वह भी बता देंगे।

Now, Sir, as far as buy back of shares is concerned, I am in touch with my colleague. When Shri P. Chidambaram was the Minister of Finance, the Company Law Board was under his charge. It is now with my colleague, the Law Minister. I am in touch with the Law Minister. I did not want to repeat an empty promise in this Budget. There was no point because my predecessor had already said it in the last year's Budget. Therefore, Sir, as far as buy back of shares is concerned, we will take a view in consultation with my colleague, the Company Affairs Minister because it lies within his jurisdiction and he must be consulted in the process. So, it is nothing, I mean, we are not doing anything to artificially depress the market just as we will not do anything to artificially prop up the market. The market has its own discipline. The market behaves in its own way.

The other point which was made was in regard to the assumptions made in the Budget. Various hon. Members said, `You have made assumptions. You said that you are going to spend more money but it is not going to come true.' This was the criticism which was made. I am surprised that among others, Shri P. Chidambaram also made that criticism. Here I have got some figures. He said, `Shri C. Subramaniam, when he was the Finance Minister and presenting the Budget, had very proudly presented the Budget which had crossed Rs. 100 crore because in those days Rs. 100 crore had a meaning.' He said that Shri Yashwant Sinha is the first Finance Minister, who is presenting the Budget which has crossed Rs. 1 lakh crore as far as the Central Plan was concerned. He went on to say, `But he is not going to achieve it.'

Then, let me come to Internal Extra Budgetary Resources (IEBR). IEBR is an important part of the Central plan in every year. I have been looking at the figures. Every year, there has been a shortfall. In 1991, it was 5.7 per cent. Then it came to 6.1 per cent and 10.4 per cent. It was 5.8 per cent in 1994-95. It was 8.2 per cent in 1995-96. It was 1.28 per cent in 1996-97. It was 14.9 per cent in 1997-98. In the last dream Budget of Shri Chidambaram, the shortfall on the IEBR fund was almost 15 per cent. He said that because there was a shortfall on the IEBR, your figures would also not be achieved.

हमारी दुम कट गई तो सबकी दुम कटनी जरूरी है।

Now I cannot buy that argument. In these two years of Shri Chidambaram, the IEBR was 12.8 and 14.9 per cent. I know he faced difficulties. He himself said in this House that there were two Governments; one Government came and went and the other Government came. His whole plan was disturbed. I am not blaming him. But I would like to assure the House that the plan that we have made and the plan projections that I have put before

this House are something we have every intentions of achieving. I would go personally after the PSUs which have to raise these international extra budgetary resources. Sir, there will be a personal monitoring at my level to make sure that they do get these resources which we have put for them in this Budget and I am quite confident that the kind of abysmal performance which has preceded in the last two years will not be repeated this year.

Again you might say that I have depressed the expenditure and I have raised the revenue. I have again looked at all these figures carefully. Now I must make my projections. Every Finance Minister has the right to make projections and the House has the right, the country has the right and the people have a right to judge whether those projections are genuine, realistic or not. I would like to tell you there have been shortfalls. In 1993-94, Dr. Manmohan Singh, presented a Budget where he said that the fiscal deficit would be of the order of 4.6 per cent. What was the fiscal deficit at the end of the year? It was 7.4 per cent. Things went wrong. He could not control the situation. So the fiscal deficit went way beyond 7.4 per cent. Shri Chidambaram had said last year that he would control the fiscal deficit at 4.5 per cent. There were circumstances beyond his control. He could not do anything and the fiscal deficit had gone up to 6.1 per cent. Now I will take the fiscal deficit at 5.6 per cent. I could have also gone back to 5 per cent. I could have impressed a number of rating agencies and international investors by saying that it is going to be five per cent. I could have gone back to that. But I wanted to be realistic and that is why, I have fixed it at 5.6 per cent. And I intend not only to keep it there but also I want to improve upon that performance. If 5.6 per cent at the end of the year becomes six per cent, I will be a very sad person. But if it goes back to 5.3 to 5 per cent, then I will come before this House and say we have been able to do well. That is the kind of approach that I have in this Budget.

I had looked at the expenditure GDP figures. I have looked at the tax GDP figures and there is nothing absolutely to suggest that any of these figures are unrealistic. I will not take the time of the House in repeating those figures.

Now in the debate, every Member, who spoke from the Opposition parties and some from this side, expressed concern in regard to sanctions. What is going to be the impact of sanctions? How are we going to meet the challenge of sanctions? This is what was pointed out. I have some figures. I again do not want to blame anyone. But I would like to say that there was a pressure. The rupee, the capital market and every other issues have been raised. Why did the rupee come under pressure? Why did the capital markets depress?

Sir, if we have globalised our economy in the last seven years, if we have gone global then I have said this in the other House than we cannot just say that we will take whatever is beneficial to us and we will reject what is adverse. We have to take the good with the bad.

Is it because of my Budget that the Hangseng in Hongkong has fallen? Is it because of my Budget that the Yen has touched an all time low against the dollar, to l46 Yen? It was less than 100. Shri Natwar Singh would remember that there was a time when the Yen was against the dollar and it had come down below 100 Yen per $. Today it has gone up to l46. East Asia melted down. We are all aware of what happened and what is happening to East Asia. If we are a global economy, all these things are going to impact upon us. They will create pressure and we will have to find solutions to them. It was not because of sanctions alone that this is happening. It is because of a very peculiar situation obtaining in East Asia.

MR. SPEAKER: Shri Yashwant Sinha, one minute. Hon. Members, at 3.30 p.m. the House has to take the Private Members' Business and Resolutions. The reply of the Finance Minister is not yet completed. If the House agrees we shall take up the Private Members' Business after the House passes the Demands for Excess Grants and the Appropriation Bills. Please continue, Mr. Minister.

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): I suggest that the Private Members' Business may be taken up after the Discussion under Rule l93. We have been waiting for so many days. You were good enough to include it.

MR. SPEAKER: Shri Jaipal Reddy, please understand. There is no time for the Discussion under Rule l93 now. It will remain alive for later consideration in consultation with the BAC.

SHRI S. JAIPAL REDDY : No, no, you have made a solemn promise to discuss it, after what happened in Maruti.

MR. SPEAKER: Please continue, Shri Yashwant Sinha. Shri Jaipal Reddy, you must understand.

SHRI S. JAIPAL REDDY : What is the difficulty? We can go back to the discussion after one hour.

MR. SPEAKER: Let the reply be complete.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): After the reply is over the Discussion under Rule l93 should be taken up.

SHRI YASHWANT SINHA: I was saying that there have been pressures on the rupee. Shri Deora will recall that in February l996 the rupee had touched a level of Rs.38 to a dollar; Rs.38 to a dollar in February 1996. We were aware of the pressure which was created on the rupee as a result of East Asian melt down in November 1997. We are aware of the steps and measures the UF Government had to take in January 1998 in order to arrest the decline. Shri Jaipal Reddy a Member of that Cabinet is sitting in the House. These things happen and it is the duty of the Government of the day to ensure that orderly conditions prevail and I would like to assure this House and, through this House, the people of this country that this Government is all determined both to maintain the stability of the currency as well as the stock market. We will do whatever it needs to be done in order to ensure that.

I would like to point out one thing. The risk premium at the secondary market has jumped by about 200 to 250 points following the East Asian prices. It had jumped, however, by about 100 points after the imposition of the sanctions. But it is now running by about 50 basic points compared to March 1998.

A question was raised about the sanctions. My colleague the Commerce Minister said that I would deal with in reply to the Budget debate. The sanctions have been imposed. But the only country in the world which has imposed sanctiones is the U.S.A. No other country has imposed sanctions. Other countries for their own reasons may have deferred or frozen the overseas development assistance that they extend to this country. But no other country has said that it was imposing sanctions on India.

countries for their own reasons may have deferred or frozen the overseas development assistance that they extend to this country. But no other country has said that it was imposing sanctions on India.

It is only the United States which has a law which makes it mandatory for them to impose sanctions and the U.S. has imposed that sanction. But the U.S. has not, till date, defined the scope of that sanction. Now, when I am told have I not factored the sanctions into my Budget, then what do I do? What was the choice before me? The choice was that I could have gone to the hon. Prime Minister; I could have come before this House and I would have said that I am postponing presentation of the Budget until the U.S. defines the scope of its sanctions; until the other countries make clear how they are going to deal with us, and,then, I will come with my Budget. (Interruptions).

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): No one wants to postpone it.

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): You could have a contingency plan. (Interruptions). SHRI YASHWANT SINHA: I am saying that I have been asked why I have not factored the sanctions in my Budget. I could not have. There was no way in which I could have because none of my budgetary figures are going to be affected by either U.S. sanctions or because of deferment of the loans temporarily by any other country. Everyone knows that we have a long pipeline.

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आपका बजट राम राज्य लाएगा। कहां से लाएगा, यह तो बताइए।

श्री यशवंत सिन्हा अंत में, जब खत्म करेंगे तब बोलेंगे न।

I would like to assure the House, through you, Sir, that there is nothing which could have compelled me to factor the impact of sanctions or the deferment of loans in this Budget because no on-going project has been stopped and all the disbursements are going on as usual. Yes, I have said, 50 basis point. Some impact might be there after the sanctions are defined on commercial flows and I will take care of that.

I would like to say to this House, through you, Sir, when the sanctions come, when the world unites to make life difficult for India, then will that be a time when we shall be divided between the Treasury Benches and the Opposition? Would not this nation stand up as one person and face the challenge which the world shall throw upon us? That is the way in which this country shall face the question of sanctions.

Now, it has been pointed out that this Budget is inflationary.

कीमतें बढ़ जाएंगी, बढ़ गई हैं।

Now, those who know about these things would know that there are various factors which affect the rate of inflation. One of them is a supply of money, M-3 as it is called. Unfortunately, last year, it went up beyond the target which had been fixed. It grew by something like 17.5 per cent. We all know that M-3 impacts with a lag and that lag may well be there this year. I am not denying it. (Interruptions). This year, as far as M-3 growth is concerned, we are determined to keep it at the target level of 15 to 15.5 per cent. This is about M-3.

Then, I will come to growing rate of wholesale price. It has gone up. It was something like 5 per cent; now it has gone up to about 6.5 per cent. I have gone into the whole question in some detail. I find that there are two items which have contributed to this growth in inflation, that is, vegetables and fruits. Why only vegetables and fruits? Potato alone has gone up by 315 per cent. Kumari Mamata Banerjee was making that point yesterday.

Yes, 315 per cent because it had been a bad year. We all know, we are aware of the unseasonal rains, the continuance of the cold spell, as a result of which these produces have been affected and as a result of which the prices have gone up. But the beneficiary is the kisan of this country. Yes... (Interruptions).

SOME HON. MEMBERS: No.

SHRI YASHWANT SINHA: Yes.

AN HON. MEMBER: Beneficiary is the middleman, not the farmer.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, last year there was a glut of potato crop. The potato crop had rotten in the fields. The farmers ran from pillar to post. They did not get the proper price. They suffered huge losses. But then this is seasonal.

AN HON. MEMBER: Last year potato was selling at Re. 1 per kilogram.

SHRI YASHWANT SINHA: Yes, sometimes the farmer loses because there is a glut, sometimes the farmer gains because there is short supply. This is what has happened. I have carefully looked at the rate of inflation and the commodity price index and I would like to assure the House that apart from fruits and vegetables and some edible oils, there is absolutely nothing in the rate of inflation which suggests that there is a secular growth upward. There is no secular growth.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (PANSKURA): Excuse me, Shri Sinha.

SHRI YASHWANT SINHA: I am not yielding, Madam. I lose my chain of thought.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Have you consulted Mrs. Sinha about the daily expenditure?

SHRI S. JAIPAL REDDY : He will not consult her. She belongs to our party.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, there is nothing which points to a general direction in rise in prices. These are seasonal factors. We will get over them and we will keep the prices under control.

It has been pointed out by many Members that the Budget is anti-farmer. How is it anti-farmer? We have not looked at the whole slew of schemes that I have proposed in the Budget for the farmers. I have a small note here from a report which said that a very eminent scientist, Shri M.S. Swaminathan, while talking about this Budget, had said that: "This Budget will impart growth to the rural economy, to agriculture." That is his opinion. He does not belong to the BJP or to the ruling coalition.

Now, why am I being criticised? One point was picked up, that is, urea. In deference to the wishes which have been expressed by the Members on this side and in deference to the wishes of Shri Murli Deora who has some potted plants in his apartment in Mumbai, the Government has decided to withdraw even that 50 paise per kilogram which was there...(Interruptions).

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): राजेश जी, तालियां तो बजाइये न।...(

Interruptions).

एक माननीय सदस्य : यह हमारी वजह से विथड़ा हुआ है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : किसानों के दबाव के आगे आपको इसको वापस करना पड़ा है, इसका हम स्वागत करते हैं।

(Interruptions)

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : इन्होने कर तो दिया, इनको धन्यवाद देना चाहिए।...(

Interruptions)

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): हमारी बात ऐसे ही मानेंगे तो तालियां बजती रहेंगी। हमारी बात नहीं मानेंगे तो तालियां नहीं बजेंगी।...(

Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I can understand the discomfiture of some sections in this House but we decided that we would not let that small, little thing remain between a pro-farmer budget and us and, therefore, we have taken this decision in the larger interest of the farming community...(Interruptions)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आपने कुछ दिया नहीं, जो बढ़ाया था, उसे हमारे दबाव पर वापस कर लिया।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने दिया क्या? आपने जो बढ़ाया, उसे वापस ले लिया।

... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): मुलायम सिंह जी, इन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। कम से कम इतना तो बोल दो।

... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला): मुलायम सिंह जी, आपने बजट को पढ़ा है क्या?

MR. SPEAKER: Shri Rajveer Singh, please sit down.

... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Speaker, it has also been said that the Budget militates against the interest of the common man. Now, I can anticipate that the definition of the common man might vary, but there are whole lot of things in this Budget. The first thing is micro-banking. Why have I given so much importance to micro-banking in this Budget? Because it was not possible for the common man, the common person in the village to go and secure a loan of Rs. 500. I know of people in the area in which I live. There are widows and other women who would work during the day, who would go from field to field to collect vegetables and sell them in the nearest urban conglomerate, but they will not get Rs. 500 to buy vegetables. There are artisans, there are craftsmen and there are weavers who want to buy tools and set up their own little shop and workshop, but they will not get Rs. 2,000 or Rs. 5,000 from the bank because they do not have any maan-baap. That is why, I have introduced this concept of micro-banking.

I have said that we will do it through self-help groups. I know that it is not physically possible for any bank to have so many people who can go into into every rural area. So, we will organise them. Sir, I call upon all the Members of this House that when they go back to their constituencies, they should talk about this scheme of self-help groups. Let us form those self-help groups. Let us involve the NGOs. Let us set up new NGOs so that the poor people, the common people in the villages and rural areas ....(Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): There is nothing new. This is something which we are having from the time of Indiraji.

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): यह कोई नई बात नहीं है, यह मध्य प्रदेश में चल रही है।

... (व्यवधान)

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, nothing is ever new. This is something which we want to push forward in a very big way. Somebody was saying that there was nothing big in this Budget. He said so because this is something which will not appear to be big. If two lakh families are covered in the rural areas, it may not be big for them; it is big for me, it is big for us. Therefore, this is what we are doing.

Regarding safe drinking water, our Government has assured this House with all the emphasis at our command that we shall see that there is not a single village in this country which does not have potable water in the next five years. We wish to attack this problem as strongly as possible, and ensure that we provide drinking water. .... (Interruptions)

श्री नरेन्द्र बुडानिया : राजस्थान में आपकी सरकार है और वहां लोग प्यासे मर रहे हैं। वहां लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, उनकी आंखों से पानी गिर रहा है।

... (व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : इसलिए कि भारत सरकार ने पैसे नहीं दिये।

... (व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, I would like to draw your attention in this regard ....(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not do this. Please have order in the House. No more clarifications please.

... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: I am coming to that. We have had discussions on the suggestions that I have made in this Budget in regard to public sector undertakings.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): You have scheme for providing drinking water etc. for rural poor people....(Interruptions)

MR. SPEAKER: He is not yielding. Please take your seat.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Where the State Government is not interested in providing that sort of a facility, what action will be taken by the Government of India? ....(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, please take your seat. He is not yielding.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, when it came to public sector reform and when it came to insurance, it was exactly the point at which our friends from the Left Parties got off the aircraft of Shri Murli Deora because he was supporting these measures in the Budget.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): That was his personal view.

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Speaker, Sir, I would like to say and I would like to assure Mamtaji also that it is not the intention of the Government to close any undertaking which can be revived and we shall do all that is within our power to make sure that closed undertakings are revived. In order to make that happen, in less than three months that we have been in office, we had already taken a decision to revive - Prof. Soz is not here; he was talking about Jammu and Kashmir - the Watch Unit of the HMT in Srinagar. We are spending Government's money to revive that unit. We have taken a decision to convert loans of Rs.791 crore into non-cumulative preference capital shares and give a fresh loan of a huge amount to revive the Visakhapatnam Steel Plant which was in difficulty.

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): What about the modernisation of IISCO?

SHRI YASHWANT SINHA: That is also under our consideration.

Sir, we have restructured the main frame of the Computer Unit of the Electronics Corporation of India and I am personally looking into every case of a public sector undertaking where it can be revived. But I would like to plead before you that it has been said that a unit cannot be revived by all studies repeatedly carried out by independent people.

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): It is the State Government.

SHRI YASHWANT SINHA: Yes. (Interruptions) What do we do on that?

---

*Not recorded.

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हाः आप क्यों बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। आपकी रुचि की बात है, उसी पर बोल रहा हूं।

... (व्यवधान)

लालू जी आप बाद में बोल लेना

... (व्यवधान)

SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE (BERHAMPORE) (WB): Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister should make a comment on the National Textiles Corporation. (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Pramothes Mukherjee, he is not yielding. Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, we have offered a very interesting, a very attractive package to the workers. (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : बैठे-बैठे ही सुन लीजिए

... (व्यवधान)

आप लोग बोलेंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। मंत्री जी मैं आपकी मदद कर रहा हूं। कलकत्ता को और चेन्नई को नम्बर वन सिटी बनाने का वादा किया है, क्या बजट में उसके लिए प्रावधान है?

श्री यशवंत सिन्हाः वे बन गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): यह काम तो काफी पहले हो गया है।

SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE : Sir, the Minister should make a comment about....(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Pramothes Mukherjee, he is not yielding. Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, he has spoken. I have not spoken. I did not interrupt him. He was speaking last night. Did I interrupt him when he was speaking? Why is he interrupting me? (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Pramothes Mukherjee, please take your seat.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the point which I would like to make is that if a worker wants to work we have offered him a very attractive package for him. We all want him to work. Nobody is happy when we take the salary home to him and say: "there is no work for you, you just remain idle, sit at home and do not do any work." This is not the kind of society that we want to build and therefore, I had announced a package. Now we are trying to improve upon that package. I would like to take this House into confidence and inform the House that the Prime Minister has already appointed a Group of Ministers to go into that package to make it more attractive so that there is absolutely no problem and, wherever it is necessary, in public interest to take such decision keeping in view the interest of the workers uppermost in our minds, it is only in those cases that such a step will be taken. I would like to assure the House that we are not anti-worker in any way and it will be entirely wrong to suggest that.

SHRI YASHWANT SINHA: It is my privilege to yield to her ... (Interruptions).

SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): You are always yielding to that side. Why are you not yielding to this side? ... (Interruptions).

SHRI SATYA PAL JAIN (CHANDIGARH): She is a lady. She has been given the right... (Interruptions).

SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE : Mr. Minister, I would request you to make a comment on the National Textile Corporation... (Interruptions). People are dying of starvation... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Mukherjee, please sit down.

... (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, they are spoiling the situation ... (Interruptions). Sir, I want to assure the hon. Members from Bengal... (Interruptions).

SHRI N.K. PREMCHANDRAN : Sir, who is she to assure us?... (Interruptions).

KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, they have spoiled the situation... (Interruptions).

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, on the question of exports, a number of Members made the points. Shri Murli Deora also referred to it. He said that we are not giving importance to exports. I would like to inform the House that this is one of those rare occasions where the Exim Policy preceded the Budget. Normally, the Budget comes first and the Export-Import Policy comes later. Due to the peculiar situation obtaining this year, my colleague, the Minister for Commerce announced the Export-Import Policy first in April and the Budget came later in the month of June. A number of very significant steps have been announced in the Export-Import Policy. Exports are very important for us. Therefore, there is no way in which the topmost attention and priority will not be given to exports. In the slew of measures which have been announced by the Governor, Reserve Bank of India yesterday, export credit has been made cheaper and we are committed to doing everything which is within our power to see that India's exports pick up. It is not a fantastic news but it is re-assuring that as against minus ten per cent growth last year in April, this year, at least, there has been a positive growth of two per cent. As the year goes on, I am quite confident that we shall be able to do better on the export front with the kind of measures that we have in mind.

श्री लालू प्रसाद : सीमेंट का दाम बढ़ गया, कड़वे तेल का दाम बढ़ गया, एडिबल ऑयल का दाम बढ़ गया, कमरतोड़ महंगाई है। कुछ गरीब जनता के लिए भी बोलें।

श्री यशवंत सिन्हाः रात के तीन बजे तक बैठकर बजट को डिसकस किया, तब बोलना था।

श्री लालू प्रसाद : महंगाई के बारे में भी बोलिए।

... (व्यवधान)

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, every policy must be judged by its implementation. I agree with that. If we fail on the implementation front then this Budget will not succeed ... (Interruptions).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, it is highly objectionable. Every now and then he is interrupting.

श्री लालू प्रसाद : मिट्टी के तेल के लिए नहीं बोले, मिठाई का दाम बढ़ गया, यह महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए हम वाकआउट करते हैं।

15.59 hrs.

(At this stage Shri Lalu Prasad and some other hon. Members left the House)

16.00 hrs.

Sir, I will just finish in five minutes.

Sir, with a view to better implementation, what is it that we are going to do? I have said in my Budget Speech and I would like to draw the attention of this House once again that this whole concept of Plan and non-Plan, this whole concept of Capital and Revenue in our Budget is absolutely a distortion. Therefore, this need a fresh look. I have said in my Budget Speech that we propose to appoint a Task Force, which will look into the concept of Plan and non-Plan and Capital and Revenue. We will have two `Heads'. One `Head' will be `Development', and another `Head' will be `Non-Development'. This will clearly show the distribution of Government expenditure between development and non-development.

We have also said that there are a plethora of schemes that are Centrally-sponsored. We all, representing the people of our constituencies here, are aware of the fact that if you go and ask any officer in the field, he will not be able to name those schemes, much less implement them. Therefore, Sir, we have decided that we will adopt a uniform pattern. We will decentralise the planning process. There is no way in which anyone sitting in Delhi should decide whether a village should have a road first or a school building first or should have drinking water first or should have any other facility first. Therefore, this is a responsibility which must be given to the democratic institutions at that level, and we must have faith in those democratic institutions. Therefore, we wish to decentralise expenditure and we wish to decentralise the authority further. This also will be covered by the Task Force.

Then, there are a whole lot of employment schemes. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not disturb him. Please take your seat.

SHRI YASHWANT SINHA: We have decided that there will be two types of schemes -- the self-employment scheme and the wage employment scheme.

Now, Sir, I will come to some other important things which I have to say. Many hon. Members have expressed concern about the likely impact of the special additional customs duty of eight per cent that I have proposed in my Budget. Some Members have suggested that I should withdraw this levy, and some others have suggested that while it is desirable in principle, the incidence may be reduced, lest it result in a significant rise of cost of production. I have also received a large number of representations from various sectors of trade and industry in this regard. They have generally asked that while the rate of special additional duty may be reduced to about four per cent at par with Central Sales Tax rate, the levy may be extended to traders as well. This is their suggestion. I am grateful for the views expressed by the hon. Members. I have given my very careful consideration to this matter taking into account the views expressed on behalf of various sectors of industry also. I find that the consensus is that while the levy is justified to afford a level playing field to the domestic producers, the cumulative burden of duty at the rate of eight per cent may be a bit too high, especially in view of the development on the rupee front in recent days. In deference to the wishes expressed by the hon. Members and balancing the interest of domestic producers and the consumers, I propose to reduce the rate of duty from eight per cent to four per cent.

Sir, demands have also been made from some quarters for imposing this duty on traders. I am unable to do so for the simple reason that the justification for this levy lies in imposing duty where local taxes are not payable and traded goods pay local duty, therefore, I have decided to exclude them from this levy.

The exporters have also represented to me that the levy may affect their export effort. This is not my intention. As I have said, it is our policy to maximise exports. I have, therefore, decided that the special additional duty will not apply to inputs and capital goods imported under special export-related schemes.

I have also decided to allow drawback of the special additional duty of customs which might be levied at the time of import for export-production. For this purpose, I will move an amendment in the Finance Bill at the appropriate time.

I am just expressing the intent.

These changes will be notified with effect from tomorrow in regard to this.

Now I would also like to inform the House, through you, that I have received a number of representations against the proposed withdrawal of exemption from withholding tax on interest paid by Indian companies on foreign bonds. While the general principle of extending withholding tax requirements is sound, many investors and organisations have argued that this exemption is a longstanding practice and this removal will disturb financing arrangements for projects, especially in infrastructure in environment which is somewhat volatile at this moment.

Keeping in view the importance of strengthening investment activities and specially investment in infrastructure, I reconsidered the matter and decided to continue this exemption. Necessary amendment will be brought in the Finance Bill.

I have also received a number of other representations on a specific indirect tax changes proposed in the Budget. (Interruptions) We shall study these representations very carefully and consider any modifications are needed at the time of consideration of the Finance Bill.

In the meantime, I have instructed the Revenue Department to take special care to ensure that newly assessable units are not put to any inconvenience. Therefore, until a decision in regard to the representations received has been taken by us ...

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Will they do it now?

SHRI YASHWANT SINHA: Not for the time being. That is what I mean by inconvenience.

Therefore, these are some of the decisions which we have taken. When we come to discuss the Finance Bill, I will, if there are issues after consideration, come forth with amendments as usual on our own. Now that we have removed some of the issues in this Budget which were impinging on some specific interests, I think that there will be absolutely no objection even from the point of view of the Opposition benches in getting this Budget now passed unanimously.

MR. SPEAKER: I shall now put the Demands for Excess Grants (General) for 1995-96.

The question is :

"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to make good the excess on the respective grants during the year ended 31st day of March, 1996 in respect of the following demands entered in the second column thereof: -

Demand Nos. 13, 14, 17, 65 and 81."

The motion was adopted.

_____

">